खण्ड–07 सत्र–02 अंक–10

मंगलवार 09 मार्च, 2021 18 फाल्गुन, 1942 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड–07 (भाग–1) में अंक 09 से अंक 13 सम्मिलित है।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन
सचिव
C. VELMURUGAN
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary(Editing)

विषय–सूची

सत्र–2 (भाग–1) – मंगलवार, 09 मार्च, 2021/18 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक–10

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	3–4
2.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	6–12
3.	वार्षिक बजट 2021–22	12–56
4.	वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण	57
5.	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण	57–60
6.	विनियोजन (संख्या–1) विधेयक 2021 का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण	61–63
7.	कार्यमंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर सहमति	65
8.	01–04–2021 से 31–03–2022 की अवधि के लिए वित्तीय समितियों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	65–66

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र – 2, मंगलवार, 09 मार्च, 2021 / 18 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक 10

दिल्ली विधान सभा
सदन पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए

1	श्री अजेश यादव	16	श्री महेंद्र यादव
2	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	17	श्री नरेश यादव
3	श्रीमती ए धनवती चंदीला ए	18	श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
4	श्री अजय दत्त	19	श्री प्रलाद सिंह साहनी
5	सुश्री आतिशी	20	श्री प्रवीण कुमार
6	श्री अब्दुल रहमान	21	श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
7	सुश्री भावना गौड़	22	श्री प्रकाश जारवाल
8	श्री बी.एस.जून	23	श्री ऋतुराज गोविंद
9	श्री धर्मपाल लाकड़ा	24	श्री रघुविंदर शौकीन
10	श्री गिरीश सोनी	25	श्री राजेश गुप्ता
11	श्री हाजी युनूस	26	श्री राज कुमार आनंद
12	श्री जय भगवान	27	श्री रोहित कुमार
13	श्री जरनैल सिंह	28	श्री शरद कुमार चौहान
14	श्री करतार सिंह तंवर	29	श्री सोमनाथ भारती
15	श्री मुकेश अहलावत	30	श्री सही राम

31	श्री एस.के.बग्गा	41	श्री ओमप्रकाश शर्मा
32	श्री विनय मिश्रा	42	श्री पवन शर्मा
33	श्री वीरेंद्र सिंह कादियान	43	श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
34	श्री अभय वर्मा	44	श्री राजेश ऋषि
35	श्री अनिल कुमार बाजपेयी	45	श्री शिव चरण गोयल
36	श्री अजय कुमार महावर	46	श्री सौरभ भारद्वाज
37	श्री जितेंद्र महाजन	47	श्री विजेंद्र गुप्ता
38	श्री महेंद्र गोयल	48	श्री विशेष रवि
39	श्री मदन लाल	49	श्री संजीव झा
40	श्री मोहन सिंह बिष्ट	50	श्री सोम दत्त

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–2, मंगलवार, 09 मार्च, 2021/18 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक–10

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष : मुझे श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय सदस्य से नियम–54 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। कल माननीय उप–राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया था और आज माननीय उप–मुख्यमंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। माननीय उप–राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और बजट पर तीन दिन तक चर्चा होगी। माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए किसी अन्य प्रस्ताव की अनुमति देना अभी संभव नहीं होगा। मैं पिछले सत्र के दौरान भी इस सम्बन्ध में कई बार माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर सदन में विचार नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस बारे में तर्क–वितर्क से सदन का समय व्यर्थ न करें।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके इस स्टेटमेन्ट से सहमत नहीं हूं। ये लोकतंत्र में जिस तरह से चर्चा का गला घोटा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : विशेष उल्लेख नियम–280 माननीय सदस्यगण आज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : 280 को तो पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। क्वेश्चन आवर होता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : विजेंद्र जी, मैंने बड़े सम्मानपूर्वक कहा है।

श्री विजेंद्र गुप्ता : आपने कहा है आगे नहीं होगी चर्चा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैंने कब कहा चर्चा नहीं होगी। मैंने कहा तीन दिन तक चर्चा का समय है हमारे पास। चर्चा होगी। मैंनें कहा है। मैं फिर दोहरा देता हूं। थोड़ा सा सुनने का भी वो रखें। मैंने कहा है तीन दिन चर्चा होगी। उस दौरान आप अपने विषय उठा सकते हैं और मैं अनुमति दूंगा। मैंने कब कहा, मैंने कब कही ये बात? ये लिखित है। पढ़ा हुआ है। ये लिखित है। मैंने जो पढ़ा है। ऐसे न मेरे कान में डालिए कुछ भी। भई हो गया। देखिए, आज बजट पेश हो रहा है। बिष्ट जी मैंने आपकी बात सुन ली। पढ़ लिया मैंने।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : ध्यानाकर्षण का मतलब क्या होता है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया सारा। वो देख लिया मैंने सारी बातचीत कर ली।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : दो चीजें होनी है।

माननीय अध्यक्षः विशेष उल्लेख नियम–280, माननीय सदस्यगण, आज माननीय उप–मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आज विशेष उल्लेख के तहत उठाये जाने वाले सभी मामलों को पढ़ा हुआ माना जायेगा।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री अजय कुमार महावर : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र घौण्डा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गामड़ी घौण्डा मार्ग के चौड़ीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस मार्ग पर पहले बड़ी–बड़ी बसें चलती थीं, लेकिन धीरे–धीरे यह मार्ग संकरा हो गया है। मास्टर प्लान के हिसाब से इस रोड की चौड़ाई 100 फीट है। इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायकों ने भी इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया था। वर्ष 2012 में दिल्ली नगर निगम द्वारा इसका डिमार्केशन भी किया गया था। इस सड़क के चौडीकरण के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से भी मिल चुका हूं। इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए क्षेत्र के कुछ लोग न्यायालय में भी गये थे और माननीय न्यायालय ने भी सड़क चौड़ा कराने के पक्ष में फैसला दिया था। मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जनहित में इस सड़क के चौड़ीकरण के मार्ग में जो भी बाधायें हैं , उसको दूर कर इस सड़क को जल्द से जल्द चौड़ा करवाया जाए।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सभी सदस्यों व दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं देती हूं जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से मुकाबला किया और जीत हासिल की। मैं आज इस सदन के सामने अपनी क्षेत्र आर.के.पुरम की एक समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आदरणीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन क्लस्टर– आदर्श बस्ती–मोहम्मदपुर, लाल बहादुर शास्त्री कैंप एवं मलाई मंदिर कैंप के शौचालयों की रख–रखाव की जिम्मेदारी जिस NGO को दी गई थी, उसके समय पर बिजली का बिल न अदा करने के कारण, इन शौचालयों में पिछले काफी समय से बिजली के कनेक्शन कटे हुए है। ऐसे में बस्ती के बच्चों एवं महिलाओं के लिए शौचालय का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। कृपया इसका समाधान निकाला जाए एवं महिलाओं के शौचालय में बाहर के साथ–साथ प्रत्येक क्यूबिकल के अंदर भी डस्टबिन व लाइट होनी चाहिए ताकि हमारी महिलाएं : हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बच्चियों को अंधेरे में शौचालय का प्रयोग करने में संकोच न हो और वे सैनिटरी–नैपकिन आदि कूड़ा इधर उधर न फेंके।

श्री जय भगवान : आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान बवाना विधान सभा के शाहबाद डेरी, सेक्टर–24, 25, 26 व बवाना जे जे कॉलानी की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमे सट्टा, स्मैक चरस, अफीम, गंजा, दारू का कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है।

12 1/2 गज व 25 गज की कॉलोनी में गरीब बस्ती के अन्दर लोग किसी प्रकार से परिवार का पालन पोषण करते है। यहां पर सट्टा, स्मैक चरस, अफीम, गंजा, दारू का कारोबार काफी ज्यादा मात्रा में दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये लोग आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत एवं खतरनाक हैं। दिल्ली पुलिस प्रशासन की शह

की वजह से यह और ज्यादा फल–फूल रहे हैं अगर हम इन्हें यहीं पर रोक ले तो शायद हमारा कल अच्छा होगा। नशे की लत से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इसकी वजह से लोग हत्या, आत्महत्या, लड़ाई, झगड़ा, खून–खराबा, करने को तैयार है एवं घर व परिवार में इनकी वजह से क्लेश बढ़ गया है। श्री मान जी, यह युवा पीढ़ी इस उभरते हुए भारत की ताकत, देश का भविष्य, आने वाला कल, आपके हमारे बुढ़ापे का सहारा इस युवा पीढ़ी को अंधेरे रास्ते पर जाने से रोकें, इन्हें सही रास्ता दिखाए जिससे ये कल का भविष्य बने, यह मामला मानव सुरक्षा से जुड़ा हुआ है । सदन के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई कराए और दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस संदर्भ में दिशा–निर्देश जारी करें, जिससे इस युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : आदरणीय महोदय, आज दिल्ली में पी डब्ल्यू डी के अंतर्गत रख–रखाव में आने वाली सड़को पर लगातार कब्जा बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ रोडों पर इन्क्रोचमेंट की वजह से लोगों का पटरियों पर चलना दूभर हो गया है। जब पी डब्ल्यू डी से कार्रवाई की बात की जाती है तो पी डब्ल्यू डी कहती है कि इन्क्रोचमेंट हटाने की शक्ति एम सी डी के पास है और चालान करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ पी डब्ल्यू डी को इन्क्रोचमेंट हटाने के लिए भी एम सी डी को लिखना पड़ता है तथा भ्रष्ट एम सी डी उन कब्जो व अनाधिकृत कार्यों को हटाने में पैसा खाकर बिल्कुल सहयोग नहीं करती है तो क्या हम दिल्ली को ऐसे में एम सी डी के भ्रष्टाचार के हवाले छोड़ सकते है? एक तरफ जहॉ एम सी डी का कर्तव्य है कि अनाधिकृत कब्जे न हो और व्यवस्था बनी रहे तथा इन्क्रोचमेंट जिसे एम सी डी ने पी डब्ल्यू डी के साथ मिलकर हटाया है वह फिर वहॉ न हो, इसके लिए क्षेत्रीय एस एच ओ की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तय की है। परन्तु पुलिस एवं एम सी डी दोनों बीजेपी के हाथों में होने की वजह से दिल्ली बुरी तरह से अव्यवस्थित व इन्क्रोचमेंट का शिकार होती जा रही है। अतः श्रीमान जी मेरा आपसे अनुरोध है कि पी डब्ल्यू डी को उसका अधिकार प्राप्त कराने तथा बढ़ते इन्क्रोचमेंट को रोकने पर कोई ठोस कदम उठाने का कष्ट करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जल विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र विश्वासनगर में पेय जल की भीषण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में गाजीपुर गॉव, सैनी एन्क्लेव, कड़कड़डूमा गॉव तथा कड़कड़डूमा कॉलोनी के अंदर पेय जल की भयंकर समस्या है, जहॉ पेय जल की आपूर्ति न के बराबर है और जो पानी आता भी है वह बहुत ही गंदा पानी आता है। जहॉ लोग कम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं गंदे पानी की आपूर्ति होने से लोग जल–जनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पेय जल की इस समस्या को ठीक करने के लिए पाईप लाईन को बदला जाए और पर्याप्त मात्रा में पेय जल की आपूर्ति की जाए।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुकुंदपुर स्थित समता विहार कॉलोनी में 3–4 दिन पहले घटित कानून व्यवस्था को तार–तार करने वाली उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसने दिल्लीवासियों की सुरक्षा के प्रति प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।

अध्यक्ष जी, तीन–चार दिन पूर्व रात्रि के समय हथियारों से लैस बाइकों पर सवार होकर आए लगभग 150–200 बदमाशों ने अचानक मुकुंदपुर स्थित समता विहार कॉलोनी में लगभग 200 घरों पर धावा बोल दिया। उन बदमाशों ने लोगों से यह कहते हुए कि ये घर उनके हैं, लोगों को उनकें घरों से मारते–पीटते हुए बाहर खदेड़ दिया और उनके घरों पर कब्जा कर लिया। ये बदमाश निरंकुश होकर वहां के निवासियों के साथ निर्दयता से मारपीट कर रहे थे, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। इन गुंडों ने वहां के निर्दोष लोगों में आतंक एवं अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। लोगों का यह कहना था कि ये किसी कुख्यात अपराधिक गैंग के गुर्गे प्रतीत हो रहे थे। लोग अचानक हुए इस हमले को समझ ही नहीं पा रहें थे। इस घटना के दौरान पुलिस नदारद थी। बाद में वहां दो दिनों तक कफ्र्यू भी लगा और 2–4 अपराधी पकड़े गए हैं परंतु अधिकतर अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं माननीय मंत्री

जी से अनुरोध करूंगा कि देश की राजधानी में हुई इस बड़ी अप्रत्याशित अपराधिक घटना का संज्ञान लेते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनके विरूद्ध न्यायिक कार्यवाई करने हेतु दिल्ली पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही, इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति न होने के लिए भी दिल्ली पुलिस द्व ारा सदन को आश्वस्त किया जाना चाहिए।

श्री सोम दत्त : आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सिविल डिफेंस वालंटियर भर्ती प्रक्रिया को Transparent बनाने हेतु सिविल डिफेंस भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनिंग व भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाये। इसमें बहुत खामिया/corruption है। धन्यवाद

श्री अभय वर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीनगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास मार्ग का सौन्दर्यीकरण का काम करवाया जा रहा है। अक्तूबर, 2020 के बाद से इस सड़क का निर्माण कार्य बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, जिससे वहॉ के निवासियों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदेश देकर इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवायें। इस सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे खड़े हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि इस सड़क का सौन्दर्यीकरण करते समय इन बिजली के खंभों को हटाकर बिजली के तारों को भूमिगत करवाया जाए। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करता हूं कि सड़क की चौड़ाई में किसी भी प्रकार की कमी न की जाए, क्योंकि इस रोड पर ट्रेफिक बहुत अधिक होता है, जिससे जाम लगता है ।

श्री पवन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र की अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी कानून व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यदि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में हुए पिछले 6 महीने का डाटा निकाला जाए तो हमारे विधान सभा क्षेत्र

में सर्वाधिक अपराधिक घटनाएं घटित हुई होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मेनस्ट्रीम मीडिया में आई कुछ प्रमुख घटनाओं का ही जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। 27 अक्टूबर को भरोला गॉव में, सुशील की निर्मम हत्या कर दी जाती है तथा उसके परिवार पर हमला किया जाता है। इसी क्रम में 10 अक्टूबर को, आर्दश नगर निवासी 18 साल के नौजवान राहुल राजपूत जो कोचिंग पढ़ा कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था बीच–बाजार में उसको पीट–पीट कर हत्या कर दी गयी। 16 नवम्बर को जी ब्लॉक, जहॉगीरपुरी में घर के सामने ही असामाजिक तत्व शराब पी रहे थे, जब राजेश ने उनको मना किया तो उसकी हत्या कर दी जाती है, लगभग 15 दिन पहले ही जी–ब्लॉक जहॉगीरपुरी में खुलेआम गोली चला कर एक नौजवान अप्पू को जान से मारने का प्रयास किया गया। अभी इसी 27 फरवरी को अपनी ही गली में सिमरनजीत कौर जी की हत्या चैन–स्नैचिंग करने वालों ने कर दी। अगर गिनाने लगूं तो महोदय सत्र का पूरा दिन ही आदर्श नगर की घटनाओं का जिक्र करते–करते खत्म हो जाएगा।

प्रत्येक दिन मेरे कार्यालय में हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता व RWA के पदाधिकारी चैन–स्नैचिंग, गाड़ी चोरी, बैटरी चोरी, आदि तमाम अपराधिक घटनाओं को लेकर आते है। मै माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर गली में कैमरा लगवाने का काम किया। महोदय लगभग उपरोक्त सभी घटनाओं की विडियों फुटेज दिल्ली सरकार के CCTV कैमरों में उपलब्ध है किन्तु दिल्ली पुलिस की लापरवाही व अकर्मण्यता ने जहॉ पुलिस वालों को घूसखोर व निकम्मा बना दिया वहीं मनचलों व अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। महोदय मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि आपकी निगरानी में एक समिति का निर्माण होना चाहिए जो समय–समय पर पुलिस के कार्यों की समीक्षा कर सकें तथा शोषित व पीड़ित व्यक्ति को अविलम्ब न्याय मिल सके।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जो 1000 नई सी.एन.जी. चलित लो–फ्लोर बसें खरीदी गयी है और इनके वार्षिक देख–रेख के लिए अनुबंध किये गये हैं, उसमें भारी घोटाले की बू आ रही है।

उपरोक्त निर्णय दिनांक 22.12.2020 से लेकर 21.02.2021 के बीच दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड की जो बैठकें हुई हैं, उनमें लिया गया है और जिनकी अध्यक्षता माननीय परिवहन मंत्री ने की थी। अध्यक्ष जी, हैरानी की बात तो यह है कि उनके मिनट्स न तो दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट पर और न ही पब्लिक डोमेन में डाले गये। इससे पहले दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड की जितनी भी बैठकें हुई हैं, उनके मिनट्स दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सादर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिनांक 22.12.2020 से लेकर 21.02.2021 के बीच दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड की बैठक के मिनट्स परिवहन विभाग/दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट पर डलवाये जाएं तथा उनके इन बसों की खरीद और वार्षिक देख–रेख अनुबंध से संबंधित दस्तावेज हमें उपलब्ध करवाए जाएं। जिन्होंने दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड की बैठकों के मिनट्स को वेबसाइट पर डालने में जान–बूझकर कोताही की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण। अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप–मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2021–22 का बजट पेश करने जा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस सदन में अपनी सरकार का लगातार सातवां बजट पेश करने का मुझे मौका मिला है। ये बजट मैं ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब हम भारत के लोग अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021–22 जिसके लिए मैं ये बजट पेश कर रहा हूं उसमें हमारे देश की एक सबसे ऐतिहासिक तारीख होगी 15 अगस्त, 2021 यानि हमारा 75वॉ स्वतंत्रता दिवस। अध्यक्ष महोदय, मैं आज महसूस कर रहा हूं और ऐसा मुझे भरोसा है कि सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य भी यही महसूस कर रहा होगा कि हम सब ऋणी हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के जिनकी निःस्वार्थ कुर्बानियों की वजह से आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहें हैं। जिस सदन में हम बैठे हैं ये सदन, ये रूम, ये कक्ष 1912 से 1926 तक अखण्ड भारत का संसद भवन रहा

है। ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि इसी कक्ष में बैठकर आज हम देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की सेवा में चर्चा और निर्णय ले पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से 75 साल पहले हमारी आजादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक शत–शत नमन करते हुए ये बजट प्रस्तुत करता हूं और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूं कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों के द्वारा आजाद वतन को लेकर देखे गये सपने के निर्माण में हम कुछ कदमों का भी योगदान कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने ये तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन–बान–शान के साथ मनायेंगे और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरूआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायको के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त, 2021 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा। देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से सम्बन्धित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं । हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है। पुनर्विलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव यानि कि आजाद हिन्दूस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहॉ देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं India @ 75 के celebration के साथ–साथ India @ 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेन्स का सातवॉ बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेन्स में मात्र अगले वित्त वर्ष या अगले कुछ वर्षों के लिए नहीं बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केन्द्र बिन्दु होगी, हमारी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली । जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आन्दोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी हमारी दिल्ली बनी होगी। उस वक्त की चुनौतियॉ थीं अंग्रेजों की दमनकारी नीति और सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है लेकिन राजनैतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण आज भी जारी है। किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। अब मैं आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों से मेरे बजट वक्तव्य में परम्परा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ ऑकड़ें प्रस्तुत करता हूं। सामान्यतः ये जो ऑकड़ें होते हैं ये हर साल और अगले वित्त वर्ष से सम्बन्धित ऑकड़ें और कुछ अनुमान होते हैं। मैं आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर आपकी अनुमति से मेरे वक्तव्य के इस वाले भाग में जहां हम आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, दिल्ली के पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त सी रोशनी डालना चाहता हूं। 1901 में हमारी दिल्ली कुल 4 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर थी। 1911 में जब अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया तो यहां आबादी थोड़ी–थोड़ी बढ़नी शुरू हुई लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी देखी गयी 1941 से 1951 के बीच में और खासतौर से 1947 के बाद माइग्रेशन के दौरान जब पाकिस्तान से लाखों परिवारों ने दिल्ली में आकर अपना घर बनाया। 1947 में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी उस वक्त यहां की आबादी थी 6 लाख 96 हजार।

1951 की जनगणना जब हुई तो ये बढ़कर 17 लाख 44 हजार हो गयी। पिछले 75 साल में हम दिल्लीवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए ये ऑकड़े इसलिए रखे क्योंकि ये एक जर्नी को समझने के लिए और उसके आगे एक विजन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ग्रोथ है इसको देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है और आज इस बजट में 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो सम्मान से जीने के लिए सुविधायें चाहिए होंगी, उसकी नींव आज हम इस बजट में यहां पर रखने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से दिल्ली की एसजीडीपी के ऑकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं और उस वक्त की केन्द्र सरकार के लिए शायद ये सम्भव भी नहीं रहा होगा कि वो दिल्ली के लोगों के विकास के लिए अलग से एसजीडीपी के ऑकड़े इकट्ठा करें क्योंकि उनके पास पूरे देश के लिए काम करने का समय होता है लेकिन वर्तमान सरकार जब से बनी है जो वर्तमान व्यवस्था के तहत 1993–94 से दिल्ली की एसजीडीपी के ऑकड़े उपलब्ध हैं। 1993–94 में दिल्ली की एसजीडीपी 20,992 करोड़ रूपये थी। लगभग 21 हजार करोड़ रूपये थी जो बहुत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्तमान में 7 लाख 98 हजार 310 करोड़ रूपये पहुंच चुकी है। इसी तरह 1993–94 से दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 18,967 रूपये थी स्थिर मूल्यों पर जो 2019–20 में 2,74,671 पहुँच चुकी है। 93–94 में 18 हजार 9 सौ 67 से आज हम 2 लाख 74 हजार 671 की पर–कैपिटा इन्कम पर खड़े हैं अध्यक्ष महोदय। ये दिल्ली जो है इस कैपिटा इन्कम में स्थिर मूल्यों में देश में नंबर दो पर है। प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की पर–कैपिटा इन्कम 2020–21 में 3,54,004 रुपए हो गयी है। दिल्ली की जो पर–कैपिटा इन्कम है प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान वित्त वर्ष में 1,27,768 रुपए के नेशनल एवरेज से 2.77 टाइम्स ज्यादा है। दिल्ली का पर–कैपिटा इन्कम। 2020–21 के दौरान के एसडीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर 3.92 परसेंट और स्थिर मूल्यों पर 5.68 परसेंट की कमी देखी गयी कोविड महामारी और इससे रोकथाम के लिए जो उपाय किये गये ये उसका असर हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री, श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को उनकी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दूरदर्शिता से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक ये मैं एक बड़ा लक्ष्य अपने सदन के सामने रख रहा हूँ। सरकार के सामने रख रहा हूँ। इसपे काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे हुए नागरिक के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो। इसको संभव बनाने के लिए हमें अपने नागरिकों की आय में लगभग 16 गुना की वृद्धि करनी होगी। ये एक मुश्किल लक्ष्य तो है, लेकिन मुश्किल लक्ष्य पर इस विधान सभा ने पिछले सात साल में बहुत काम किये हैं, ये भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में जिस तरह केजरीवाल मॉडल आफ इकोनोमिक्स के तहत् दिल्लीवासियों के हर महीने के खर्च में पानी के महंगे बिल की जगह पानी के जीरो बिल आये हैं। बिजली के महंगे बिल की जगह 75 परसेंट आबादी के बिजली के बिल जीरो आए हैं। बच्चों के महंगे एजुकेशन की जगह सरकारी स्कूलों में जीरो खर्च पर शानदार एजुकेशन मिल रही है और खास तौर से महिलाओं के लिए कहीं भी आने जाने में अब बस का खर्चा जीरो हो गया है। इन सबके परिणाम से प्रत्येक परिवार की आय में हर महीने की जो बचत हो रही है, उसका असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप पड़ेगा और हमें उम्मीद हैं अगले सेंसस के जो आँकड़े आएंगे, वो पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आए हुए आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा इंडिकेटर होंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2020–21 जो वर्तमान वित्त वर्ष है, उसके लिए कुछ रिवाइज्ड एस्टीमेट सदन के समक्ष रखता हूँ। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 59 हजार करोड़ रुपए का रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रस्तावित है। जबकि बी.ई में हमने इसके लिए 65 हजार करोड़ रुपए का अनुमोदन लिया था। 59 हजार करोड़ रुपए का आर.ई पिछले साल में व्यय किये गये 51,186 करोड़ रुपए से 15.26 परसेंट अधिक है और 59 हजार रुपए के आर.ई में 46,215 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के तहत् 12,785 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत् हैं। आर.ई में कैपीटल एक्सपेंडिचर 16,930

करोड़ रुपए से घटकर 12,785 करोड़ रुपए आ गया है और इसकी वजह जाहिर है कोरोना और लॉक डाउन के कारण जो कैपीटल वर्क्स में धीमापन आया। कई महीनों तक कोई गतिविधि नहीं चली, वो रहा है। इसी तरह आर.ई में इस्टिब्लिशमेंट अदर एक्सपेंडिचर के तहत् इस साल बी.ई में 35,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,900 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और इसके पीछे मुख्य वजह है कोरोना संबंधी व्यय। रिवाइज्ड एस्टिमेट में 2020–21 में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 23,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बी.ई में इसके लिए 25,900 करोड़ रुपए अनुमोदन किये गये थे।

महोदय, एक्सीलेंट एंड इफेक्टिव फाइनेंसल मैनेजमेंट, इसके जरिये हमने अपने बकाया ऋण को मार्च, 2020 तक 31,135 करोड़ रुपए रखा है। दिल्ली का बकाया ऋण वर्ष 2014–15 में 5.90 से घटकर वर्ष 2019–20 में जीएसडीपी के 3.74 परसेंट हो गया है। 2020–21 के बारे में रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आँकड़ों के अनुसार दिल्ली का लोन जीएसडीपी रेशियो देश के बांकी सब राज्यों की तुलना में सबसे कम है। ये बात सीएजी ने भी माना था कि दिल्ली सरकार सरप्लस में चलती है। ये बात अब जो रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आँकड़े हैं, वो भी पेश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड भी रख रहा हूँ। वर्ष 2020–21 के दौरान आर.ई में 891 करोड़ 87 लाख 40 हजार रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड की आवश्यकता होगी, इसके लिए मैं सदन का अनुमोदन चाहता हूँ। अब मैं आपके समक्ष अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश कर रहा हूँ।

महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रुपए था, जो उनका बजट था 2014–15 का। मैंने अपना पहला पूर्ण बजट 2015 में जून में पेश किया था और उसमें 37,750 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय था। साल दर साल हम इनोवेटिव स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एजुकेशन, हैल्थ, अर्बन डेवलपमेंट के बहुत सारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे और इन योजनाओं के लिए अपना खर्चा बढ़ाते रहे। मैं अत्यंत हर्ष के साथ 2021–22 के लिए 69 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित

कर रहा हूँ जो 2014–15 में 30,940 करोड़ रुपए की बजट की राशि से दो गुने से अधिक है।

श्री ओमप्रकाश शर्माः 69 या 59 हजार।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः 69 हजार।

माननीय अध्यक्षः सिक्सटी नाईन, सिक्सटी नाईन।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः ये जानना सुखद होगा कि हमारी सरकार की अवधि में स्कीम्स कार्यक्रम और परियोजनाओं की बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो दिल्लीवासियों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट वर्क पर हमारी सरकार के ध्यान को ज्यादा दर्शाती है। बजटीय आवंटन के लिए दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय ये जो आज हम बजट आवंटन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार प्रति व्यक्ति व्यय पर–कैपिटा एक्सपेंडिचर 2015–16 के 19,218 रुपए से बढ़कर इस साल 33,173 रुपए हो जाने की उम्मीद है। यानि सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो पर हैड प्रति व्यक्ति इस सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो 19,218 रुपए था 2015–16 में और इस साल 33,173 रुपए हो जाने की इसकी उम्मीद है। 69 हजार करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग डिविजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और स्कीम में 55 परसेंट है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेडिचर होता है, उसमें 45 परसेंट बजट है , ये अपने आप में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसमें 51,799 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत् और 17,201 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत् रखे गये हैं। 2020–21 के बी.ई में 16,930 करोड़ रुपए कैपिटल और 48 हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत् थे। अगले साल के बी.ई में वर्तमान वर्ष के बी.ई की तुलना में कैपिटल में 2 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि रेवेन्यू 8 परसेंट बढ़ा है। 2021–22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रुपए का कैपिटल 2014–15 में 7,430 करोड़ की कैपिटल से दो गुना हो चुका है तो 2014–15 में जो कैपिटल वर्क था, उससे आज हम दो गुने पर हो गये हैं तो कैपीटल वर्क में भी दिल्ली की तरक्की में चीजें काफी आगे बढ़ी हैं। 2021–22 का प्रस्तावित बजट जो 2020–21 के 65 हजार करोड़ रुपए के

बी.ई से 6.15 परसेंट अधिक है और आर.ई जो इस साल का वर्तमान वित्त वर्ष का आर.ई है, उससे 17 परसेंट अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तावित 69 हजार करोड़ रुपए के बजट में से 43 हजार करोड़ रुपए कर राजस्व से आएगा। 1 हजार करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9,285 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग्स लोन से, 1 हजार करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 6 हजार करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेसन से, 2,088 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के स्पोंसर स्कीम्स से और केवल 657 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता और शेष राशि ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,367करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,298 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रुप में होंगे और 2,069 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट बीटीए के रुप में होंगे। इसके अलावा स्थानीय निकायों को 1805 करोड़ रुपए स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के हिस्से में उपलब्ध कराए गये हैं। हमारी सरकार इस प्रकार स्थानीय निकाय के बजट अनुमान 2021–22 में 6,172 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2021–22 के लिए कुछ प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करूंगा, जो 2021–22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आरंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि आजादी की साल गिरह की 75वीं वर्ष गांठ के अवसर पर आगामी वर्ष देश भक्ति के वातावरण से ओत–प्रोत रहेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ेगी और जैसा कि मैंने बताया कि 75 साल पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से देश भक्ति के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आगामी 12 मार्च से दिल्ली में देश भक्ति के कार्यक्रमों की एक श्रृखंला शुरू होगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन–बान–शान के साथ मनाएंगी। इस क्रम

में देश भक्ति बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ। 12 मार्च से शुरू हो रहे देश भक्ति आयोजनों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे और सिर्फ दिल्ली में नहीं आजादी के आन्दोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली का विजन इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आजादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गये उनके सपने पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्त्रोत हैं। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि ''अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है।''

आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपये बजट हम रख रहे हैं ताकि भगत सिंह जी के जीवन पर कार्यक्रमों के जरिए हम चाहते हैं कि देश की वर्तमान युवा शक्ति उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और इस भाव के साथ जियें कि

हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए

सबको जीना सिखा जायेंगे मरते–मरते।

ये न समझो कि भगत फांसी पर लटकाया गया

सैंकड़ों भगत बन जायेंगे मरते–मरते।

इस उद्देश्य के साथ एक अलग से पूरा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को समर्पित चलेगा पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूपरेखा बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह किया, वो भी अपने आप में संघर्ष, देशभक्ति और दूरदर्शिता की एक बहुत अनोखी मिसाल है। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिन्दुस्तान में जी रहे हैं जहां जात–पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों को, उनके सपनों के संविधान और हिन्दुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के

लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में बाबा साहब को याद करते हुए हरेक हिन्दुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि

'रूतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है,

ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है,

औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा,

हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है'

ये बाबा साहब की देन है इस देश की कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके ये बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलायेंगे इस पूरे वर्ष में।

अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत की 75 साल की हमारी यात्रा में हमारी पहचान का हमारे अस्तित्व का हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा 'विजयी विश्वजीत तिरंगा प्यारा, झंड़ा ऊंचा रहे हमारा'। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस महान अवसर पर, उत्सव के इस अवसर पर अपनी दिल्ली को, दिल्ली के आसमान को पूरे आसमान को तिरंगे से सजाए। हम लोग जब दिल्ली के कनाट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सबने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं कोई भी हिन्दुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओत–प्रोत हो जाता है। हाल ही में मैंने एनएसयूटी में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देखकर भी वहां से निकलने वाले द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा मुझे भी कहा मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए तिरंगे को लहराते हुए देखकर एकदम मन देशभक्ति से

रोमांचित हो उठता है। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी के 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हरेक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं न कहीं आसमान में तिरंगा ऊंचा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम। अध्यक्ष महोदय, आसमान की ऊंचाईयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह से सजायेंगे कि आप दिल्ली में भले ही एक या दो किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकले। आपको कहीं शानदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और आपके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे, आपके अंदर देशभक्ति का रोमांच भड़क उठे। इसके लिए बजट में मैं 45 करोड़ रुपये का अलग से प्रस्ताव कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हरेक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरूआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गयी है, इसके तहत रोजाना एक पीरियड़ देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हरेक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओत–प्रोत हो। हर पढ़ा लिखा आदमी देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाकर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पर बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति पर दाग लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए। वो आपसी भाई–चारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखें। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, गांधी जी से लेकर बाबा साहब तक, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की परिकल्पना एक सुशिक्षित राष्ट्र के रुप में की थी। देश की 95 प्रतिशत आबादी आजादी के 75 साल के बाद भी उस क्वालिटी एजूकेशन तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी हमारी आजादी के मतवालों ने कल्पना की थी। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हमें शिक्षा को जन–आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसे जन–आंदोलन बनाने की शुरूआत दिल्ली से करेंगे। तो हम पढ़े–लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे, जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वालिंयटर प्रोग्राम इस साल से शुरू किए जाने की संभावना है और हम चाहते हैं कि आजादी के दीवानों ने जो सपना देखा था सुशिक्षित भारत का उसे पूरा करने के लिए देश का हरेक युवा आगे आए और अपने से अगली पीढ़ी के एक–एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाए।

अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में हमारे बच्चों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में हम एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्मड फोर्सिज प्रिपेरटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल है लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं है। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्मड फोर्सिज प्रिपेरटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की रेगुलर पढ़ाई के साथ–साथ उनको एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवार के सम्मान और मदद के लिए एक करोड़ रुपये की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अगले वित्त वर्ष 2021–22 में मैं 26 करोड़ रुपये का प्रावधान रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश में हुए प्राचीन भारत में हुए हमारे मन और शरीर पर हुए अनुसंधान रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के आधार पर उस वक्त जब दुनिया में माडर्न लैब टैक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान को उन गहराइयों तक जाकर अनुसंधान कर लिया था। जैसे हम आज की परंपरागत भाषा में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आज तक समझना संभव नहीं हो सका है। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को नाम दिया था ध्यान और योग की परंपरा। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों साल में दुनियाभर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान और ध्यान योग के रुप में उपलब्ध कराया है। मैंने लॉस एंजिल्स के वीडियो देखें हैं जहां पर हजारों लोग हर सप्ताह ध्यान करने के लिए पार्कों में उमड़कर आते हैं हर सप्ताह समाज में एक परंपरा बनी हुई है। हमारे यहां एक–दो दिन के कार्यक्रम के रुप में योग को जीवन में उतारने के कार्यक्रम तो चलते देखे हैं। लेकिन सरकार के स्तर पर समाज को जोड़कर निरंतर रुप से ध्यान और योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना नहीं रही है जिसके कारण जरूरत और जिज्ञासा होने के बाद भी एक आम नागरिक को योग और ध्यान का वांछित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली के अलग–अलग कालोनियों में नागरिकों को मांग पर उन्हें ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे। इन ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स को दिल्ली सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए मैं अलग से 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल तक के आजाद हिन्दुस्तान में भारतीय गीत–संगीत और कलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें साल में फैस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फैस्टिवल के तहत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इनका थीम आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल की आजाद यात्रा और 100 साल तक के सपने को, रखा जाएगा ऐसी हमारी योजना है। दिल्ली सरकार का अध्यक्ष महोदय, हमेशा प्रयास रहा

है कि हमारे बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हमारे शहर में उपलब्ध है। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। अब आजादी की हीरक जयंती हम मना रहे हैं तो हम अपने बुजुर्गों के सम्मान को कैसे भूल सकते हैं। 75वें वर्ष के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कदम ये भी होगा कि हम अपनी पूरी दिल्ली के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने के लिए पूरी दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित करेंगे और ये कार्यक्रम दिल्ली में सक्रिय विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों के साथ मिलकर आयोजित होंगे। इसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उन प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करूंगा, जो 2021–22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है और मैं समझता हूं कि ये जैसा मैंने कहा कि 100 साल की दिल्ली 100 साल का हिन्दुस्तान कैसा होगा उसकी आधारशिला है।

सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बात करूंगा। 2020 का वर्ष ऐसा आया कि पूरी दुनिया में 2020 का साल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम हो गया। दुनिया में शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा दौर आएगा दुनिया में। लेकिन शायद यही हिन्दुस्तान है। हमारे हिन्दुस्तान के शायर वक्त से आगे चलते हैं। हमारे हिन्दुस्तान के शायरों ने इसकी कल्पना में कुछ लिख दिया था बहुत पहले। बशीर बद्र साहब ने कोरोना के लिए शायद एडवांस में लिख दिया था कि 'कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से'। कोरोना के समय लॉकडाउन, दो गज की दूरीः

कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से,

ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो।

ये नए मिजाज की दुनिया है इसमें फासले से मिलना कानूनी जरूरत है और कानूनी बात नहीं मानने पर जुर्माना है नए मिजाज की दुनिया में। अध्यक्ष महोदय जैसे

शायर ने पहले लिखा शायद दिल्ली सरकार भी जाने–अनजाने में इसकी पहले से तैयारी कर रही थी। हमने शिक्षा के साथ–साथ हमेशा इस सदन से बजट पास किया है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करने पर उसको आधुनिकतम बनाने पर उसको हर आदमी को सहजता से उपलब्ध कराने पर लगातार काम किया तो ऐसा लग रहा है जैसे जाने–अनजाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसके लिए तैयारी की जा रही थी और हमने 6 साल में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया उसकी प्रगति ने शायद दिल्ली के लिए कोरोना महामारी के दौरान इसके सफल प्रबंधन को संभव बनाया। आजादी के बाद 1951 के पहले जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उस समय दिल्ली में कुल 12 सरकारी अस्पताल थे 1951 के आंकड़ों के अनुसार और कुल मिलाकर 17 डिस्पेंसरी थी अध्यक्ष महोदय। आज इस समय दिल्ली में 38 मल्टीस्पेसिलिटी अस्पताल हैं, 181 ऐलोपेथिक औषधालय हैं, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक हैं, 27 पॉलीक्लीनिक हैं, 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 46 आयुर्वेदिक केन्द्र हैं, 22 यूनानी केन्द्र हैं, 107 होम्योपैथिक औषधालय हैं, 78 Day Shelter Homes हैं मेडिकल के लिए, 311 Night Shelter Homes को कवर करने वाली 22 Mobile Clinics लगी हुई हैं और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिक दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं। महोदय मैं इन सब संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टर, नर्स और सभी अस्पताल कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने महीनों तक 24 घंटे दिल्ली वासियों की खूब सेवा की और बाकी राज्यों से भी जो लोग दिल्ली में आए उनकी भी खूब सेवा की और उन्हें निर्बाध चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई। उनका योगदान इस महामारी के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता थी कि दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी कोविड के दौरान चरमराती स्वास्थ्य की हालत को देखा उन्होंने और उनसे सबक लिया और समय रहते कोविड के लिए होम आइसोलेशन की नई अवधारणा को दिल्ली में शुरु करवाया। देश का पहला प्लाजमा बैंक भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शुरु करवाया और जरूरतमंद रोगियों को निशुल्क प्लाजमा उपलब्ध कराना शुरु हुआ। होम आइसोलेशन और प्लाजमा दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इनोवेटिव थी और जिनकी वजह से दिल्ली का कोरोना मैनेजमेंट

बाकी लोगों के सीखने के लिए एक मिसाल बना एक प्रेरणा बना। अध्यक्ष महोदय, अब वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए आशा की एक नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45 हजार लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है और जिसे एक–दो दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60 हजार वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो समान्यतः प्राइवेट हास्पिटल में, बाजार में भी ढ़ाई सौ रुपये में उपलब्ध होगी लेकिन अध्यक्ष महोदय हम सब साथियों की विधान सभाओं में जिनको हम रिप्रजेंट कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं एक महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाउं और आजादी के 75 वें साल में ये सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपये की राशि अलग से प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड से मिले हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1293 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। ये परियोजनाएं हैं ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर, विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देना, नये अस्पतालों और नये रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14 हजार से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। बुराड़ी में, संजीव भाई बैठे हैं। बुराड़ी में 768 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण का काम पूरा हो गया है और इसे कोविड के लिए 450 बिस्तरों के साथ खोल दिया गया है। इसी तरह अंबेडकर नगर अस्पताल भी जुलाई 2020 से कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। द्वारका में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल 1241 बिस्तरों की क्षमता के साथ अगले साल से अपना काम करना शुरु कर देगा।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी को छोटी–छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें आम आदमी को इसके लिए हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक की एक नई अवधारणा शुरु की थी। आज दिल्ली के अलग–अलग मोहल्लों में लोग अपने आसपास वाकिंग डिस्टेंस पर अपनी छोटी–छोटी बीमारियों के लिए उन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जिसके लिए उन्हें या तो पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता था या जेब से मोटे पैसे खर्च करके किसी प्राइवेट डॉक्टर के सामने खड़ा होना पड़ता था। आज इस सदन में मैं इसी दिशा में इसी परिकल्पना पर आधारित एक नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लीनिक शुरु किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुलकर अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती हैं। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है तो अपने आसपास कोई Women Specialist ढूंढ़ लेती है लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, हमारी एक बड़ी आबादी कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती हैं। दिल्ली सरकार अब ये जिम्मेदारी निभाएगी कि दिल्ली की हर महिला के आसपास उसकी वाकिंग डिस्टेंस पर उसके बहुत नजदीक उसके पास वूमेन रोग स्पेस्लिस्ट हों महिला रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उसको उपलब्ध हों और संबंधित बीमारियों के टैस्ट और उसकी दवाइयां भी वहां पर निशुल्क उपलब्ध हों। पहले चरण में दिल्ली के अलग–अलग हिस्सों में 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक शुरु किए जाएंगे और इनको क्रमशः बढ़ाकर हर वार्ड में कम से कम एक क्लीनिक तक हम लेकर जाएंगे। अपनी आधी आबादी को सम्मान पूर्वक स्वस्थ रखने की दिशा में 75 साल की आजादी के इतिहास में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम मैं समझता हूं ये होगा और इस कदम को उठाने के लिए 75 वीं सालगिरह से बढ़िया और मौका क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से 75 वें वर्ष में की जा रही है वो है दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा और इसके साथ ही दिल्ली में Online Health Information

Management System(HIMS) स्थापित किया जाएगा। इसमें दिल्ली के नागरिकों की बीमारी का उनके इलाज का उनकी test report का उनकी दी गई दवाइयों का पूरा डेटा बेस इस एचआईएमएस में होगा और आदमी को एक हेल्थ कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा ताकि उसको जब भी अपने इलाज के लिए कहीं अस्पताल में जाना पड़े तो वो पुराने टैस्ट, पुराने रिकॉर्ड, पुराने वो बस्ते लेकर जाने की जरूरत नहीं है वो केवल अपना कार्ड लेके जा सकता है और पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन डॉक्टर के पास उपलब्ध होगा ये सारी सूचनाएं वहां पर डेटाबेस में उपलब्ध होंगी। पहले चरण में इस योजना को दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में पॉली क्लीनिक, मोहल्ला क्लीनिक इत्यादि में लागू करेंगे, एचआईएमएस से जुड़ेंगे और उसको Geotracking के जरिए रोगियों की पहचान और tracking में भी मदद मिलेगी और इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो परिवारों की अनुवांशिक बीमारियां हैं उसका रिकॉर्ड भी फिर हर डॉक्टर के पास में अपने पास आने वाले हरेक मरीज के बारे में से पहले होगा और उसको उसके बारे में बेहतर डिसीजन लेने में सुविधा मिलेगी।

दिल्ली में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागरिकों को तुरंत और सुरक्षित इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरु कराई थी 'दिल्ली के फरिश्ते, इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल लेकर जाता है तो उसको कानूनी कार्यवाही पूछताछ नहीं होती उसको 2 हजार रुपये एक इनाम में दिये जाते हैं और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसके इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। ये योजना बेहद सफल रही है और इसकी वजह से 10,600 नागरिकों की जान अभी तक बचाई जा चुकी है और चारों तरफ इस योजना की खूब तारीफ हो रही है। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले वो नागरिक जिनका कोई बड़ा टैस्ट होना है जैसे की एमआरआई होना है, सीटी स्कैन होना है और सरकारी सुविधाओं में अगर लंबी लाइन है तो ये महंगे टैस्ट प्राइवेट हास्पिटल या प्राइवेट क्लीनिकल सेंटर्स से मुफ्त कराए जा सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होना है और सरकारी सिस्टम में मरीजों की ज्यादा संख्या होने के कारण ऑपरेशन की डेट उसको एक महीने से ज्यादा के समय की मिल रही है तो Kejriwal Model

of Governance के तहत उसके ऑपरेशन की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में कराई जा सकती है और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इन दूरदर्शी योजनाओं की बदौलत आज एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भार कम हुआ है वहीं आम जनता को जरूरी इलाज समय रहते मिल सका है ये योजनाएं अगले वित्त वर्ष में भी चालू रहेंगी।

बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर इलाज हरेक नागरिक का अधिकार है अध्यक्ष महोदय और आजादी के 75 वें वर्ष में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकि हरेक नागरिक अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त रह सके। महोदय मैं वर्ष 2021–22 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9934 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करता हूं जो कुल बजट का 14 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय अब मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा, पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज हम कहां खड़े हैं और जब हिन्दुस्तान 100 साल का होगा आजाद दिल्ली 100 साल की होगी तो कहां पहुंचना है इस संबंध में आजाद देश की राजधानी 100 साल में कहां पहुंचेगी इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूंगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, aided सब मिलाकर 619 स्कूल थे और इनमें से ज्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हॉयर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिलाकर हो गई है 5691। महोदय, शिक्षा पर किया गया काम Kejriwal Model of Governance के development principle की एक आधारशिला रही है और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार लगभग 25 परसेंट शिक्षा के लिए रखा जाता है ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार, दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98 परसेंट पहुंच गए ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास कीं इस बार। एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों ने नीट का exam

पास किया, ये भी एक अपने आप में रिकार्ड है। शिक्षा में जो innovations हुए उनसे प्रभावित होकर नीति आयोग की रिपोर्ट में भी माना गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर वन हैं। अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच अच्छा वातावरण और शानदार results, इसके बाद हमें education की quality पर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने नर्सरी से आठवीं के बच्चों के लिए Happiness Class की रोजाना शुरूआत की है जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी की feelings को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने लगे हैं। happiness के अन्तर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए कि Happiness Class के अन्तर्गत 16 लाख बच्चे अपनी क्लास की शुरूआत 5 मिनट के mindfullness meditation से करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना meditation का ये प्रयोग अपने आप में अनूठा है और happiness के अंदर देशभर के राज्यों की भी रूचि बढ़ रही है और international education systems की बहुत रूचि बढ़ रही है तो उसको देखते हुए हम इसकी international knowledge sharing के लिए International Cell की स्थापना इसमें कर रहे हैं। नवीं से बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए Entrepreneurship Mindset पाठ्यक्रम शुरू किया गया है इसका मकसद है बच्चों में critical thinking, problem solving, risk taking, self management जिन्हें हम 21 century skills कहते हैं उनका विकास करना। Entrepreneurship कार्यक्रम के तहत इस साल हम 11वीं, 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए 2 हजार रूपये प्रति बच्चे की सीड–मनी उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को अवसर देंगे कि वो अकेले या छोटे–छोटे समूहों में बिजनेस ideas लेकर आएं, कुछ काम करने के, कुछ बिजनेस, कुछ इनवेस्ट करने के ideas लेकर आएं और अपनी क्लास और अध्यापकों के सामने उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद आसपास के जो लोकल entrepreneurs हैं उनके साथ उनकी scrutiny कराएंगे और वहां से पास हुए प्रोजेक्ट को फिर हम प्रति बच्चा 2 हजार रूपये सीड–मनी के हिसाब से फंड करेंगे और ताकि बच्चे के अंदर risk taking capability बढ़े, उसको बिजनेस करना, innovative तरीकों पर अपना काम करने का अभ्यास हो। इनमें से सफल ideas जो होंगे उनकी एक बड़ी entrepreneurship exhibition भी लगाएंगे और जो अच्छे ideas होंगे उनको अवार्ड भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति और सैनिक स्कूल एकेडमी का मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को उपर जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है वो है कि पहला है नर्सरी से आठवीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है, दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 School of Excellence स्थापित किए जाएंगे।

नर्सरी से आठवीं क्लास के लिए नए पाठयक्रम के आधार पर सिलेबस तैयार करने का काम अंतिम चरण में है और इस साल जारी की गई नई शिक्षा नीति में Early Childhood Education जिसे स्कूल एजुकेशन का एक अहम हिस्सा माना गया है, हमें खुशी है कि दिल्ली सरकार के पिछले बजट में नई शिक्षा नीति के आने से पहले हमने इसकी घोषणा की थी और आज हम Early Childhood को मेनस्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नए सिलेबस में प्राइमरी क्लास से ही बच्चे को रखने की जगह उसके व्यक्तित्व विकास पर जोर देने का सिलेबस बना रहे हैं। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड इसकी घोषणा अभी माननीय मुख्यमंत्री ने केबिनेट में अप्रूवल के बाद की। अपना शिक्षा बोर्ड शुरू करने के पीछे भी मकसद ये है कि अभी तक जो पढ़ाई रटने के आधार पर होती थी उसे बच्चों की अपने विषयों की समझने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बनाया जा सके। दिल्ली केबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है और इसके तीन लक्ष्य हमने रखे हैं पहला कि हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों और आने वाले समय में देश के हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हों। दूसरा, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनें और तीसरा कि जब वो पढ़ लिखकर आगे बढ़े तो केवल नौकरियों के पीछे न भागें, नौकरियां क्रिएट करें, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको तैयार करे। तो ये इस बोर्ड को बनाने के लक्ष्य हैं। इस बोर्ड में हम अन्तर्राष्ट्रीय collaborations करके ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके standard International standards के हों और शुरू में इसमें 20–25 स्कूलों से शुरू करेंगे और उम्मीद ये है कि अगले 4–5 साल के अंदर जैसे जैसे इसके results आएंगे, इसके नतीजे आगे बढ़ेंगे, बाकी स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी इसमें शामिल होंगे।

इसी तरह से School of Specialized Excellence बनाने के पीछे भी हमारा मकसद है कि अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को नवीं, दसवीं, ग्याहरवीं और बारहवीं में excellence स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे के पढ़ा सकें। इस योजना के तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में नवीं से बारहवीं क्लास के 100 स्कूलों में School of Specialized Excellence खोले जाएंगे और इसमें वर्तमान में चल रहे प्रतिभा विकास विद्यालयों और 5 साल पहले खोले गए School of Specialized Excellence भी शामिल किए जाएंगे। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में School of Excellence का जो मॉडल दिया है, अब बाकी जगह भी उससे inspire होकर, उसको replicate कर रहे हैं। खुद केन्द्र सरकार ने इस साल पूरे देश में 15 हजार School of Excellence बनाने की घोषणा की है। तो हमारे लिए यह अच्छा है कि जो दिल्ली का School of Excellence का जो मॉडल था वो केन्द्र सरकार को भी प्रेरित कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, देश की प्रतिभाओं को चिन्हित् करना और उन्हें पूरे संसाधन लगा के दुनियाभर की बेहतरीन प्रतिभाओं के सामने मुकाबले में खड़ा करना यही हमारे लिए देशभक्ति की राजनीति है। हमारे बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देना और उन्हें दुनिया के सामने कंपीटिशन में, शान से खड़े करना हमारे लिए यही देशभक्ति की राजनीति है। 75 साल पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी तरफ से बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर देशभक्ति की यही राजनीति हम श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी ने हमें मजबूरी में ही सही, टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करना खूब सिखाया और विशेषकर एजुकेशन में। हमारे टीचर्स ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के ऑनलाइन एजुकेशन को सच करके दिखाया। इसमें मैं ऐसे अध्यापकों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने संभवतः जिन्दगी में कभी स्मार्ट फोन इस्तेमाल नहीं किया होगा लेकिन जब वक्त आकर पड़ा तो उन्होंने अपने बच्चों से मदद ली, अपने यंग टीचर्स से मदद ली लेकिन उन्होंने टेक्नॉलॉजी को सीखा, online education को सीखा और लगभग एक साल तक अपने बच्चों को online classes से पढ़ाया। ऐसे टीचर्स के प्रति हम

आज सम्मान व्यक्त करते हैं। कोविड की वैक्सीन आ गयी है और ये बीमारी आज नहीं तो कल, बीते कल की बात हो जाएगी लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच रहेगी। टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल एजुकेशन में हुआ उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, आगे के लिए लेकर चल रहे हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे Virtual Delhi Model School यानि कि एक ऐसा स्कूल जिसमें चार–दीवारियां नहीं होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, पढ़ाई होगी, बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, एन्रोलमेंट होंगे, एग्जामिनेशंस होंगे लेकिन चार–दीवारियां नहीं होंगी, ये Virtual Model School होगा, दिल्ली का एक अपने आप में एक अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला Virtual Model School होगा। इस स्कूल की डिजाइनिंग पर काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से ये अपना काम करना शुरू कर दे। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सब बच्चों को anywhere living, anytime learning, anytime testing की सुविधा देकर उसके तहत सीखने का अवसर देंगे।

इसके साथ ही स्कूल में नई बिल्डिंग बनवाने, नए कमरे बनवाने, स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने के जो काम कोविड के कारण धीमे हो गए थे उन्हें अब वापस तेजी से शुरू कर दिया है। इनमें से कई अपने अंतिम चरण में हैं। शिक्षकों को आईआईएम, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, फिनलैंड, सिंगापुर प्रशिक्षण हेतू भेजने की जो योजना पहले चालू थी उसको अब वापस पुनः चालू कर रहे हैं।

अब मैं थोड़ी सी बात अध्यक्ष महोदय उच्च शिक्षा की करना चाहूंगा, स्कूल की मैंने बात की। आजादी के बाद से दिल्ली की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो गुणवत्ता के लिहाज से शानदार काम हुआ लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से उच्च शिक्षा के अवसर दिल्ली में हर बच्चे को उपलब्ध हों, उसपर हम 75 साल में कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए मैंने कहा कि हमको बात करनी चाहिए कि हम कहां पहुंचे, कहां कमी रह गयी और कहां जाना है। तो 75 साल में हम हायर एजुकेशन में satisfactory काम दिल्ली में नहीं कर पाए हैं, जितनी आबादी हमारी

बढ़ी है उस हिसाब से हम बच्चों को quality education उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हालांकि पिछले 6 साल में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली में हायर एजुकेशन की सीट्स में 36.42 प्रतिशत और टेक्निकल एजुकेशन में 66.44 प्रतिशत सीटों की वृद्धि हुई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। गुरू गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैम्पस का निर्माण 2021 में मई तक पूरा हो जाएगा। धीरपुर रोहिणी में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नया परिसर 2023 तक पूरा हो जाएगा और इससे हमारे विद्याार्थियों को लेने की क्षमता, intake वो साढे 8 हजार और बढ़ जाएगी। Higher Technical Education के सेक्टर में Skill & Entrepreneurship University अपना काम शुरू कर चुकी है। Sports University भी अपना काम इस साल से शुरू कर देगी।

नई शिक्षा नीति के बाद हमें देश में teacher training पर बहुत जोर देना पड़ेगा। उसमें अच्छी चीज ये हुई है कि अभी तक ग्रेजुएशन के बाद टीचर ट्रेनिंग होती थी, जो बी.एड. होता था, नई शिक्षा नीति में 4 साल के teacher training के प्रोग्राम को देश में मंजूरी मिल रही है। तो इसके लिए नयी शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन के स्तर पर 4 साल की टीचर ट्रेनिंग का बी.एड. का कोर्स आ रहा है। दिल्ली सरकार इसके लिए एक अलग से 'Teachers' University' की स्थापना करेगी, इस साल इसका काम हम शुरू कर देंगे। इस यूनिवर्सिटी का काम होगा देश और दुनिया के बेहतरीन टीचर्स तैयार करने वाली यूनिवर्सिटीज जो दुनियाभर में हैं उनके साथ मिलकर दिल्ली के लिए अच्छे टीचर्स तैयार करना।

इसी तरह दिल्ली सरकार आने वाले समय में कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नई 'लॉ यूनिवर्सिटी' लाने की भी तैयारी कर रही है 'दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी' हम इसमें खोलेंगे। इससे कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के जो इच्छुक नौजवान हैं उनको और अवसर मिलेंगे।

अंग्रेजी में अच्छी बातचीत आज हमारे माडर्न जॉब्स की बहुत बड़ी जरूरत है और विद्यार्थियों के लिए एक दुखती रग रहा है। अंग्रेजी बोलने की capacity बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन ने एक नयी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत

उन्हें रोजगार की तलाश या उच्चतर शिक्षा में एडमिशन के लिए बाहर निकलने के लिए जो अंग्रेजी सीखने की जरूरत होती है उसकी अलग से क्लासिस ली जाएंगी और इसमें English Speaking Course कराने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर इसको चलाया जाएगा। इसमें अंग्रेजी बोलने के साथ साथ body language और personality development पर भी काम होगा और हमारा लक्ष्य है कि एक साल में 5 से 6 लाख विद्यार्थियों को, युवाओं को इसका लाभ मिले।

10वीं से 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को 10 लाख तक की एजुकेशन लोन पर गारंटी सरकार देती है जिससे किसी बच्चे की उच्च शिक्षा पैसे के अभाव में बीच में न छूटे। इसी के साथ 6 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से फीस का 100 परसेंट तक फेलोशिप के रूप में भी दिया जाता है, ये दोनों योजनाएं अगले साल भी चालू रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको दिल्ली सरकार पिछले 6 साल में इनोवेशन्स के रूप में शुरू कर चुकी है। मुझे खुशी है कि इनको नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया, मैं खुद अपनी सीनियर ऑफिसर्स की टीम के साथ प्रो. के. कस्तूरीरंगन जी से मार्गदर्शन के लिए बैंगलोर में जाकर मिला और मैं उनका आभारी हूं कि नई शिक्षा नीति के वो राइटर हैं, डिजाइनर हैं, इस नीति के बहुत महत्वपूर्ण पहलूओं को दिल्ली में लागू करने में वह हमारी मदद कर रहें हैं। नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए हमको दिल्ली में 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो 50 साल पुराना कानून है–दिल्ली स्कूल एजूकेशन एक्ट' उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी और एक 100 साल पुराना कानून है जिसका जिक्र मैं यहां पहले भी कर चुका हूं 'देहली यूनिवर्सिटी एक्ट' उसके तहत फिर दिल्ली में एफिलेटिंग कोलिजिज/यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जा सकती है। तो इन दोनों कानूनों को बदलने की जरूरत पड़ेगी, उसमें क्योंकि दोनों में कंटराडिक्शन है, नई शिक्षा नीति और जो हमारा 50 साल पुराना कानून है उसमें कंटराडिक्शन है दोनों जगह। तो उसको बदलने के लिए दिल्ली का जो कानून है उसको हमने नया बनाना शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार से रिक्वैस्ट किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट जो सैंट्रल एक्ट है उसको भी बदलें।

मैं अगले वित्त वर्ष के लिए शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 6 बजटों का अनुकरण करते हुए इस साल भी शिक्षा का बजट कुल बजट का एक चौथाई है, करीब–करीब एक चौथाई है।

थोड़ी सी बात अध्यक्ष महोदय मैं खेल पर रखना चाहता हूं। दिल्ली में आज खेल का एक बेहतरीन स्पोर्टस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। हमने दिल्ली के दूर दराज इलाकों में विशेषकर गांव देहात के इलाकों में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं विकसित की हैं। दिल्ली में 1951 में, अब देखिए जर्नी देखिए खेलों की, 1951 में पहले एशियाड गेम्स का आयोजन हुआ, उसके बाद 1982 में फिर से एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, 2010 में मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप और कॉमनवैल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। तो हमने अब स्पोर्टस यूनिवर्सिटी बनाई है कि दिल्ली का जो स्पोर्टस टैलेंट है वो एक साथ आए और उसकी nurture हो, वह फले–फूले। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में इंटरनैशनल मैडल विनिंग चैंपियंस हम स्पोर्टस यूनिवर्सिटी में तैयार करे।

लेकिन आज आजादी की 75 वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर मैं जब देशभक्ति बजट रख रहा हूं तो खेल को लेकर एक बड़ा सपना इस सदन में रखना चाहता हूं, इस उद्देश्य के साथ रखना चाहता हूं कि भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक हमको ये सपना पूरा करना है। सपना ये है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। 1896 में एथेंस से शुरू होकर आज तक ओलंपिक की मशाल कभी दिल्ली में आकर ठहरी नहीं है। अब अगले ओलंपिक गेम्स, 32वॉ ओलंपिक गेम्स टोकियो में होने फिक्स हो चुके हैं, उसके बाद के अगले तीन ओलंपिक्स के होस्ट कौन होंगे वो भी तय हो चुके हैं, ओलंपिक कमेटी बहुत एडवांस में चलती है। इसीलिए मैंने 25 साल बाद का सपना देखा है, आजादी के 100वें साल का सपना देखा है । हमारी सरकार ने अब खेल यूनिवर्सिटी बना दी है और हम इससे दिल्ली में एक वातावरण बनाएंगे। सपना ये है कि अगले 25 साल में दिल्ली में स्पोर्टस का इतना शानदार वातावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और आज से 12–13 साल बाद जब 2048 के ओलंपिक गेम्स की बिडिंग शुरू हो तो हम

दिल्ली के अंदर वो कोंफिडेंस पैदा कर सकें और दुनिया के अंदर ये कोन्फिडेंस पैदा कर सकें कि ओलंपिक अथोरिटी, वो दिल्ली की ओर उम्मीद भरी और विश्वास भरी नजरों से देखें और वो कहे कि हॉ दिल्ली भी दावेदार हो सकता है और उस बिडिंग में से दिल्ली दावेदार बनकर निकले और जब हम आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे हों, 100वॉ वर्ष मना रहे हो तो ओलंपिक की मशाल दिल्ली में जल रही हो, ये सपना है मेरा।

अध्यक्ष महोदय, आवास, विकास और शहरी विकास के संबंध में कुछ बातें। हमारी सरकार दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए, सड़क नाली, पार्क आदि के निर्माण से लेकर, सीवर डलवाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने के काम पर तो लगातार जोर देती रही है। हमारी सरकार बनने के पहले ये काम दिल्ली की 895 अनधिकृत कालोनियों में थोड़े बहुत स्तर पर कराया जाता था। लेकिन 2015 के बाद से दिल्ली की हर एक अनधिकृत कालोनी और झुग्गीबस्ती में ये सुविधा देने का काम तेजी से हुआ है, यह रिकॉर्ड है, संजीव भाई बैठे हैं। कभी काम नहीं हुए थे उन इलाकों में। कभी अनओथराइज्ड कहकर छोड़ दिया, कभी ये 895 में नहीं है कहकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब पूरे हुए है। अब तक दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1345 में निर्माण के काम पूरे हो चुके है या प्रगति पर है और इन कालोनियों में विकास के लिए मैं 1550 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करता हूं।

डयूसिब के सराहनीय प्रयासों से एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित कर दिया गया है। यहां 21,586 वैस्टर्न सीटस के साथ 674 जन सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। 619 झुग्गी बस्तियों में 10,16,531 मीटर्स सीमेंट कंक्रीट के फुटपाथ बनाए गए है और ढाई सौ किलोमीटर लम्बी नालियों का निर्माण कर दिया गया है और यहां रह रहे लोगों के लिए 20 नए बस्ती विकास केंद्र बनाए गए हैं।

हमारी सरकार 'जहां झुग्गी वहां मकान' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं सुल्तानपुरी के पास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए 1,060 मकान आवंटित

करने का काम अंतिम चरण में है और इसके अलावा देव नगर करोलबाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहूमंजिलें मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है।

महोदय, 2020–21 में आवास और शहरी विकास, परियोजनाओं के लिए मैं 5,328 करोड़ रुपये के प्रावधान करता हूं।

अब मैं थोड़ी सी बात जलापूर्ति और स्वच्छता पर करूंगा। दिल्ली में प्रत्येक घर को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटस में 9 प्रयोगशालाएं 24 घंटे काम कर रही हैं। पानी की आपूर्ति का हिसाब–किताब रखने के लिए 3,170 बल्क–फ्लोमीटर पहले लग चुके है और 121 बल्क–फ्लोमीटर लगाने का काम अभी अंतिम चरण में है।

अनओथराइज्ड कालोनिज में पाइप से पानी की पाइप लाइन के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और मौजूदा समय में ये सेवा 93 प्रतिशत परिवारों को करीब 14,500 किलोमीटर पाइप लाइन बिछा कर पहुंचा दी गई है। पाइप लाइन से पानी की सप्लाई के नेटवर्क में 1,622 अनाधिकृत कालोनिज को कवर कर लिया गया है। केवल 113 कॉलोनिज को छोड़कर जिनको अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं मिला है या जो वन क्षेत्र में आते हैं। अगले 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से सारी अनाधिकृत कालोनियों को पानी की आपूर्ति पाइप लाइन से सुनिश्चित कर दी जाएगी। अनाधिकृत कालोनियों में पानी की पाइप लाइन के नेटवर्क का विस्तार, जैसे मैंने बोला कर दिया है और 79 प्रतिशत आबादी इस नेटवर्क के दायरे में आ गई है।

जिन कॉलोनियों में सीवर की लाइन पिछले वर्षों में डाली गई है वहां पर 'मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना' के अंतर्गत 4.88 लाख सीवर कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की अपनी लागत पर नियमित किए गए है और ये योजना अगले साल में भी जारी रहेगी।

दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 प्रतिष्ठानों में से 585 में रेन–वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली लगा दी है और बाकी में 2021 के मानसून से पहले ये काम पूरा हो जाने की उम्मीद है।

इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का काम भी अब लगभग 99 परसैंट पूरा हो चुका है। एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ किया जा सकेगा।

महोदय, मैं दिल्ली जल बोर्ड की योजनाओ, कार्यक्रमो और परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं। इसमें 600 करोड़ रुपये 20 किलोलीटर निशुल्क पानी सब्सिडी योजना के लिए है जिसमें प्रतिमाह लगभग 6 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंच रहा है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी मुझे अपने इस प्रस्ताव में कुछ कहना है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे समय की सबसे गम्भीर, खतरनाक वैश्विक बीमारियों में से एक है और 75 साल में हम देखें तो पल्यूशन तो बढ़ा ही है। लेकिन जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हो, तब हम सब चाहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की बीमारी कोरोना की तरह से बीते हुए कल की बीमारी हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में 360–डिग्री अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को यथासंभव विस्तार देना, निर्माण स्थलों पर एंटी–स्मोग गन के इस्तेमाल को जरूरी बनाना, पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार बायो डी–कंपोजर के इस्तेमाल को पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने में प्रोत्साहन देना, मैकेनिकल रोड़ स्वीपर लगाना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट को ठीक से मैंनेज करना, खुले में कूड़े–पत्ती इनको जलाने की प्रथा पर रोक लगाना, थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करना। ये सारे ऐसे कदम हैं जो इस 360–डिग्री अप्रोच के साथ में लिए गए हैं और उनका फायदा दिल्ली को मिला है।

लेकिन इसमें सबसे बड़ा कदम है और मैं समझता हूं देश ही नहीं सम्भवतः दुनिया की सबसे प्रोगेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया

है। ये पॉलिसी अगस्त, 2020 से पिछले साल लागू कर दी गई और मैं कह सकता हूं कि इसके चलते दिल्ली देश की इलैक्ट्रिकल व्हीकल राजधानी भी अब बन गई है। इसके तहत दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में अभी तक जो डेटा है वो ये है कि हमारे यहां जितने वाहन दिल्ली में खरीदे जाते हैं उसमें से 0.2 परसैंट ई–व्हीकल खरीदे जाते थे, लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद से 7000 नए इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में खरीदे गए हैं और केवल 3 महीने के आंकड़ों की तुलना अगर मैं करूं, अभी मैंने कहा सारे व्हीकल जितने खरीदे जाते हैं उसका केवल 0.2 परसैंट ई–व्हीकल होता है। लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद अगर हम वाहनों की सेल और उसका रेशों देखे तो नई पॉलिसी आने के बाद इसका असर दिखा है कि इलैक्ट्रिक वाहनों का शेयर 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 परसैंट पहुंच गया है। ये ई–व्हीकल पॉलिसी की सफलता का एक बड़ा संकेत है और हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में कम से कम 25 परसैंट इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए।

दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर तरह के ई–वाहन के लिए रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी गई है और पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो चार्ज कैसे होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे है। जल्दी ही इनकी संख्या 500 पहुंच जाएगी। इसमें लंदन की तर्ज पर रैपिड चार्जिंग प्वाइंट्स भी बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर कम से कम एक ई–चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर ई–व्हीकल पॉलिसी आ जाती है लेकिन nitty-gritty छोड़ देते हैं। वो कहते है ना घोड़ा खरीद लिया, खूंटा छोड़ दिया, तो घोड़ा भाग गया। तो खूंटा नहीं खरीदेंगे तो फिर घोड़ा भाग जाएगा। इसलिए ई–व्हीकल पॉलिसी को बनाते वक्त ई–चार्जिंग स्टेशन उसकी बहुत बड़ी nitty-gritty है, कहां लगेंगे, कैसे लगेंगे, जो आदमी ई–व्हीकल खरीदेगा वो चार्ज कैसे करेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से एक nitty-gritty में जाके योजना बनवाई है और हमें उम्मीद है कि जब देश अपना सौ वा स्वतंत्रता

दिवस मना रहा होगा तो हमारी दिल्ली वाहनों के प्रदूषण से सौ परसेंट आजाद हो चुकी होगी। ये सपना दिखता है अध्यक्ष महोदय। मैंने अभी कहा 25 परसेंट परचेज ई–व्हीकल की हो जाए 2024 तक, अभी थोड़ा सा रिजल्ट दिखे।

मैं इसको रिसर्च कर रहा था कि ट्रांसपोर्ट का दुनिया में इतिहास क्या रहा है तो बड़ी इंट्रस्टिंग चीज एक मेरे सामने आई। न्यूयॉर्क में जब तक मोटर व्हीकल दुनिया में नहीं बने थे न्यूयॉर्क में लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, Horse Chariot और एक बड़ी आबादी थी जो Horse Chariot का यूज करके रोज सड़कों पर निकलती थी। तो जो न्यूयॉर्क का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था उसके लिए रोजाना रात को सबसे बड़ी समस्या होती थी घोड़ों की जो लीद होती है उसको रास्ते से हटाना। जो छोटे–छोटे फुटपाथ बने हुए होते होंगे डेढ़ सौ साल पहले, तो वहां से रात को घोड़े की लीद हटाने के लिए अलग से पूरी ब्रांच काम करती थी सैनिटेशन डिपार्टमेंट की वहां पर और बहुत बड़ा काम था और बड़ी प्रॉब्लम होती थी लोगों को। 1898 में न्यूयॉर्क में मोटरकार का आगमन हुआ। रिसर्च में मेरे सामने आया 30 जुलाई, 1898 को मोटर वाहनों के इस्तेमाल के पक्ष में दुनिया का पहला विज्ञापन छपा। उसकी भाषा जो मैंने अभी बात की और सपना देखा कि हमें वाहनों के पॉल्यूशन से हंड्रेड परसेंट फ्री करना है उसकी भाषा देखिए क्या थी –"get rid of horses and save costs, care and anxiety for the horses, driving motor vehicle costs about half a Cent per mile. Motor Chariot of Vinton is the best vehicle of its kind ever made" और कुछ–कुछ उन्होंने लिखा अपने विज्ञापन में। पर किसी समय दुनिया जब घोड़ो पर चलती थी उस समय ई–मोटर व्हीकल का सपना देखा गया। आज हम कह रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से मोटर व्हीकल को हटाकर हम ई–मोटर व्हीकल लायेंगे। सपना है, सपना देखेंगे तो सच होगा, किसी ने उस वक्त देखा था, आज हम यहां पर बैठके देख रहे हैं, सच जरूर होगा। ये बात मैंने सदन के समक्ष इसलिए रखी अध्यक्ष महोदय थोड़ा हल्के–फुल्के माहौल में कि हम इसकी गम्भीरता को समझ सके। 25 साल में दिल्ली के सम्पूर्ण यातायात को इलेक्ट्रिक–व्हीकल में बदलना एक मुश्किल सपना है लेकिन जरूरी सपना है।

अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ई–बसों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1,300 ई–बसों को सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है इनमें से डीटीसी की 300 ई–बसों के टेंडर हो चुके हैं और ये इसी साल दिसम्बर तक सड़क पर आ जाएगी।... 1,000 नई ई–बसें क्लस्टर स्कीम के तहत अगले साल के मध्य तक सड़कों पर आ जाएगी।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब एक साल के अंदर 1,600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है और इस साल सितम्बर तक इसमें 1,000 और बसें जुड़ जाएगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 6,693 बसों की फ्लीट हैं जो अपने आपमें दिल्ली के लिए इतिहास है। दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी बसों की फ्लीट कभी नहीं हुई। इस साल 1,000 बस और जुड़ने के बाद ये संख्या 7,693 पहुंच जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली में 11,000 बसों की फ्लीट खड़ी करें, उस पर सरकार काम कर रही है।

प्रदूषण पर काम करने के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी–स्मॉग गन लगाना आवश्यक कर दिया गया है। 2 स्मॉग टावर बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली और कानपुर के साथ मिलकर वायु, जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिए रियल टाइम एसेसमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है।

दिल्ली के ग्रीन कवर को बचाए रखने और उसमें लगातार आगे बढ़ने की दिशा में भी सरकार ने सफलता हासिल की है और देश की पहली 'ट्रीट्रान्सप्लांटेशन पॉलिसी' दिल्ली में लागू हुई है। इसका मकसद है कि दिल्ली में पेड़ जब कटे तो केवल और केवल उस परिस्थिति में कटे जब उसके अलावा कोई और चारा ना बचे, मजबूरी हो कई बार पेड़ काटना, उसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता हो तब पेड़ काटना हो, ये इसलिए लागू की गई है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने होंगे उनमें से कम से कम 80 परसेंट को ज्यूं–का–त्यूं रिट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हरेक काटे गए पेड़, जितने भी कटेंगे या जितने भी ट्रांसप्लांट होंगे उनकी जगह 10 पेड़ प्रति पेड़ उनके रिप्लेसमेंट में लगाना, तो वो

तो पहले की शर्त है वो चलती रहेगी। तो दिल्ली में बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसिस रही हैं, बहुत प्रोग्रेसिव वर्क रहा है, उसकी वजह से ग्रीन कवर बढ़कर 21.88 परसेंट हो गया है जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इन सब प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हम प्रदूषण की चुनौती से निपटने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण देकर जाएंगे।

परिवहन–

थोड़ी सी बात मैंने परिवहन की की, पर्यावरण के बाद। लेकिन अलग से परिवहन की कुछ बात और मुझे करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किए गए कुछ काम का जिक्र, मैं दोहराना चाहूंगा कि वर्तमान समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं, वाहन की ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग की प्रणाली लगी हुई है। दिल्ली में जमीन की उपलब्धता नहीं है। बसों की खरीद और परिचालन करना इसलिए एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार की दूरदर्शिता से वसंत विहार और हरी नगर में बहुस्तरीय बस डिपो के निर्माण का अब रास्ता खुल गया है और एनबीसीसी के साथ मिलकर इन डिपो का निर्माण किया जा रहा है।

दिल्ली में बसों से यात्रा के अनुभव को अच्छा अनुभव बनाने के लिए नए बस क्यू–शेल्टर का निर्माण भी किया जा रहा है और 1,397 बस क्यू–शेल्टर नए डिजाइन के साथ सरकार बनवा रही है।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए सरकार ने 95,353 ई–रिक्शा का पंजीकरण किया है, साथ ही 174 नॉन एसी मेट्रो फीडर बसें 32 रूट्स पर चलाई हैं।

दिल्ली में मेट्रो शहर की लाईफ–लाईन है, हम सब बार–बार कहते हैं। दिल्ली में 2002 में मेट्रो शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, और 18 साल के अंदर–अंदर आज हमारे पास 10 तरह की कलर कोडिड लाईन्स हैं मेट्रो की, 254 स्टेशंस हैं, साढ़े तीन सौ किलोमीटर की पटरियां हैं। चौथे चरण की योजना में 108 किलोमीटर और 78 नए

स्टेशंस अभी हमारे पाईपलाईन में हैं। आजादी के 75 साल में अगर हम उपलब्धियों की बात करें और मेट्रो की बात नहीं करें तो ये तो अधूरा रह जाएगा। लंदन में मेट्रो 1863 में शुरू हुई थी और कुल मिलाकर आज भी 400 किलोमीटर की लाईन है। टोकियो सब–वे जिसकी शुरूआत 1927 में हुई, 304 किलोमीटर कवर करती है। न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो जिसकी शुरूआत 1904 में हुई, 1,000 किलोमीटर कवर करती है। दिल्ली में मेट्रो में शुरूआत करने में हम पीछे रहें लेकिन जिस तेजी से हम आगे बढ़े हैं, हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जितनी हमारी योजनाएं अभी पाईपलाईन में हैं, इनको पूरा करते–करते हम दुनिया की सबसे लम्बी और सबसे समृद्ध मेट्रो, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को भी ले जाने वाली मेट्रो हम बन जाएंगे ।

मेट्रो के फेज–4 का निर्माण अभी अंतिम चरण मे है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों की जो संख्या हैं वो 71 लाख से पार कर जाएगी और फेज–1 के तहत 65 किलोमीटर, फेज–2 के तहत 124 किलोमीटर मेट्रो लाइन पूरी कर ली गई। फेज–3, अतिरिक्त कॉरिडोर, एनसीआर विस्तार में 160 किलोमीटर रूट की लम्बाई है, जिसमें से 157 किलोमीटर चालू भी हो गया है। मयूर विहार पॉकेट–1 से त्रिलोकपुरी खंड का शेष कार्य मार्च, 2021 तक पूरा हो जाएगा। ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार का कार्य सितम्बर, 2021 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज–4 के सभी 6 कॉरिडोर्स के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने अभी मेट्रो फेज–4 की परियोजना के प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर्स का ही अनुमोदन किया है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर, 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी, यह सुविधा अगले साल भी जारी रहेगी।

मैं परिवहन विभाग और रोड और ब्रिजिस के लिए 9,394 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव 2021–22 में करता हूं।

रोड डेवलपमेंट–

मैंने दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन में अतिरिक्त 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। करीब 1 लाख 32 हजार कैमरे, कमांड कंट्रोल सेंटर सहित लगाए जा चुके हैं और काम कर रहे हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए और उनके भुगतान के लिए अगले वर्ष में 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

हमारी सरकार लोगों को निःशुल्क वाई–फाई उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 7,000 हॉट–स्पॉट वाई–फाई के दिल्ली में लग गए हैं और काम चल रहा है उनपर, नागरिकों को निःशुल्क वाई–फाई सुविधा उपलब्ध हो रही है वहां पर ये अगले साल भी जारी रहेगी।

शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से 2021–22 में कई परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। आश्रम चौक पर अंडर पास का निर्माण कार्य जून, 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा हो जाने से मथुरा रोड (निजामुद्दीन से बदरपुर तक), आश्रम क्रासिंग पर यातायात ईजी हो जाएगा। यात्रा–समय, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। महोदय, मैं 2021–22 में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

आश्रम फ्लाइओवर के डीएनडी तक का विस्तार दिसम्बर, 2021 में पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर और सब–वे के बन जाने से नोएडा, लाजपत नगर, आईटीओ और लाजपत नगर तक सड़क का उपयोग करने वालों को आसानी होगी। मैं इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

दो परियोजनाओं का निर्माण कार्य– वजीराबाद और आजादपुर के बीच वाहनों के लिए दो अंडरपास, आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार–पथ तथा बसईदारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण मई, 2021 में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कई योजनाएं इस साल पूरी हो रही हैं।

पंजाबी बाग फ्लाईओवर से राजागार्डन, ज्वालाहेड़ी मार्केट से ज्वालापुरी रेडलाइट तक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर, मुकरबा चौक पर भीड़भाड़ कम करने की स्कीम, बुराड़ी में समानांतर सड़क पर मेन बुराड़ी रोड जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए और खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द तक रेलवे क्रासिंग पर एलसी–12 पर FOB/ RUB की 5 नई परियोजनाओं के निर्माण से इस क्षेत्र में निर्बाध यातायात होगा और लोगों का समय और पैसा बचेगा।

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को और आसान बनाने के लिए सरकार की तीन बड़ी योजनाएं हैं और अभी उनको यूटीपैक से मंजूरी का इंतजार है। ये योजनाए हैं– ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, टीकरी से आनंद विहार तक ऐलीवेटिड और टनल रोड बनेगा, नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर, सिगनेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक ऐलीवेटिड और टनल रोड है इसमें और तीसरा सिगनेचर ब्रिज से यमुना के समानांतर सराय काले खां तक आउटर रिंग रोड। अभी यूटीपैक से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा।

500 किलोमीटर सड़कों के सौन्दर्यकरण की भी तैयारी हो चुकी है और इस साल ये सड़कें सुंदर दिखनी शुरू हो जाएगी।

मैं 2021–22 में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुविधा तथा वंचित वर्ग के सामाजिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय रही है। इसके तहत 08 लाख 30 हजार लाभार्थियों के लिए दो हजार रूपये से ढ़ाई हजार रूपये तक की पेंशन दी जाती है। मैं इसके लिए 2,710 करोड़ रूपये का प्रस्ताव अगले बजट में रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं। नौकरियां गई हैं। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की योजना बनाने की जितनी जरूरत अब है उतनी पहले

कभी महसूस नहीं हुई पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी ताकि लोगों को इस विकट संकट में मदद मिल सके। इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया था उसमें interesting चीज निकल पर आई कि कोरोना से पहले फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी 26 परसेंट थी। कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी फरवरी 2021 में हमने उन्हीं महिलाओं का पुनः सर्वे करवाया तो अब वो बेरोजगारी 40 परसेंट है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं उनमें से 40 परसेंट को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इन 40 परसेंट महिलाओं में से भी 45 परसेंट महिलाएं ऐसी है जिन्होंने कम से कम बारहवीं क्लास पास कर रखी है या ग्रेजूऐशन है और इनमें से 60 परसेंट महिलाएं जो 30 साल से कम की उम्र की है। यानि युवा शक्ति पढ़ी लिखी युवा महिला शक्ति हमारी देश में अभी दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही है कोविड के बाद में और उसके सामने संकट है। तो इसको देखते हुए उन्हें इकोनॉमी में जुड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए कई नई योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से कुछ का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। एक 'सहेली समन्वय केन्द्र' हम स्थापित कर रहे हैं । इसके तहत दिल्ली के अलग–अलग क्षेत्रों में जो आंगनवाडी है वहां कुछ उनको जोड़ कर 500 आंगनवाडी हब हम बना रहे हैं, पहले से इसकी योजना थी। ये जो आंगनवाडी हब हैं ये चार घंटे तो आंगनवाडी के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद खाली रहते हैं। तो इसलिए आइडिया आया कि हम बड़ी हाईटैक बातें करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की तो इन आंगनवाडी हब को भी हम स्थानीय महिलाएं जो ये सर्वे में शामिल महिलाएं है इनके लिए चार घंटे तो ये आंगनवाडी चले और उसके बाद का बाकी समय वो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में वो आंगनवाडी हब काम करे। इसके लिए इसका नाम दे रहे है सहेली समन्वय केन्द्र। ये सैल्फ–हैल्प–ग्रुप जो आसपास के है या individual start-up करने वाली महिलाएं हैं वो महिलाएं इस सेंटर को यूज कर सकेगी और यहां इनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाऐंगे, micro-economic activity चलाने की training देने के लिए, एसएचजी समूह की बैठकों के लिए अलग–अलग कुछ facility भी देंगे। तो एक तरह से ये लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स महिलाओं के लिए बन जाएगें । दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है जैसे कि लाडली योजना चलती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए अलग से सहायता योजना

चलती है, प्रसूति योजना चलती है। महिला निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से योजना चलती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि गरीब महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता। उनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता कब, कैसे, कौन सा फार्म भरा जाए, क्या फार्म भरा जाए। तो इस समस्या के लिए 33 महिला सहायता प्रकोष्ठ महिला हैल्प लाईन, हैल्प डेस्क बनाए जाएगें जहां काउंसलर्स बैठेंगे। सरकार की इन्हीं योजनाओं के बारे में वहां आने वाले किसी भी महिला की हैल्प करेंगे। उनको गाइड करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर 'बाबा साहेब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना' प्रस्तावित है और डीएसएफडीसी ने 03 लाख रूपये वार्षिक से कम परिवार आय वाले इन शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से शिल्पी हाट बनाए जाने और पाचं साल की अवधि के लिए मासिक लीज पर उन्हें दुकानें/थड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव किया है। सरकार ने दिव्यांग लोगों की शिक्षण और पुनर्वास की जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों के पुनर्वास संस्थान स्थापना की मंजूरी दी है। सुगम्य सहायक योजना नाम से एक नई पहल दिव्यांग लोगों की गतिशीलता बढाने के लिए की गई है। इसके तहत उन्हें सहायक उपकरणों के रूप में मदद उपलब्ध कराई जाएगी और इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांग लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जाएगें। मैं समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति/जन जाति अन्य पिछडे वर्ग के कल्याण के लिए budget estimates में 4,750 करोड रूपये का प्रस्ताव करता हूं। इसी में लेबर भी है। श्रमिकों के कल्याण के लिए मानवीय श्रम कानूनों को लागू किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यबल की एक बड़ी संख्या औपचारिक अनआर्गेनाईज्ड सैक्टर में काम करती है और ये जितने कानून है ये उनकी रक्षा के लिए, उनकी योग्यताओं की रक्षा के लिए बनाए गए है। तो दिल्ली Shops & Establishment Act, 1954 के तहत seamless registration को बढावा देने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन को digitalize कर दिया है। इस साल 01 अप्रैल 2020 से 31 अक्तूबर 2020 के बीच 83,735 नई दुकानें

रजिस्टर की है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकार्ड है। स्वास्थ्य पेंशन, मातृत्व शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता, उपकरणों के लिए ऋण, विवाह के लिए आर्थिक सहायता की 18 योजनाएं दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा लागू की जा रही है। अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक 143 करोड रूपये की राशि लेबर सेस के रूप में संग्रह की गई और करीब 1,41,169 कामगार 24 जनवरी तक हमारे पास रजिस्टर्ड थे। अब तक 43,945 निर्माण कामगारों को कोरोना महामारी के कारण दस–दस हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी गई थी। 28 फरवरी तक करीब 40 करोड रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

थोडा सा जिक्र मैं पावर सैक्टर का भी करूंगा। दिल्ली के नागरिकों को अब चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है हम सब जानते हैं। बिजली लोड को नजरअंदाज करते हुए 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल की सरकार की योजना काफी सफल रही है और इसका ऊर्जा संरक्षण में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए वित्तिय प्रोत्साहन का ऐसा मॉडल चुना है जिसको सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग बिजली बचाने लगे हैं क्योंकि उनका बिजली का बिल 200 यूनिट से नीचे रखना है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 800 रूपये की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में 90 परसेंट घर बिजली की इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं और सरकार 1984 के जो दंगा पीडित हैं उनको 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 100% सब्सिडी पहले से दे रही है। वो भी इस साल जारी रहेगा। बिजली सब्सिडी योजना अदालत परिसरों में वकीलों के चैम्बर के लिए भी एक्सटेंड की गई है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनैक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है। कृषि कनैक्शन के लिए 105 रूपये प्रति केडब्ल्यूएच प्रति माह के निर्धारित शुल्क की जगह अब किसानों को केवल 20 रूपये केडब्ल्यूएस प्रति माह का भुगतान करना होगा। ये योजनाएं सुशासन के केजरीवाल मॉडल की विशिष्टताएं है। महोदय मैं वर्ष 2021–22 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3,090 करोड रूपये की राशि प्रस्तावित करता हूं। सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सौर ऊर्जा नीति' बनाई

है, जिसके तहत ज्यादातर सरकारी भवनों, स्कूलों, तकनीकी संस्थानों, अदालतों आदि की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं । जनवरी 2021 तक 4,664 सौलर यूनिट कुल 193 मैगावाट क्षमता के साथ दिल्ली में लगाए जा चुके हैं। किसानों ने भी इसमें बड़ा interest दिखाया है। 'मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना' के अन्तर्गत सौर ऊर्जा लगवाने के लिए करीब 200 एकड जमीन उपलब्ध कराई गई है। वितरण कम्पनियां अगले 05 वर्ष में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर की सुन्दरता बढाने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों से अनावश्यक तारों और केबल्स के जाल को हटाएगी। हमारी सरकार ने 11 किलोवाट के नेटवर्क को खुली तारों की जगह insulated wiring जगमगाती दिल्ली प्रोग्राम के तहत बदलने की नई योजना शुरू की है। ये योजना 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके लिए बजट अनुमान में 25 करोड अलग से रखे गए हैं। मैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,227.40 करोड रूपये की राशि प्रस्तावित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के व्यापार व उद्योग के बारे में मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा हर साल जारी की जाने वाली बीआरएपी Business Reform Action Plan रैंकिंग में दिल्ली अब 12वें स्थान पर आ गई है, पहले ये 43वे स्थान पर थी। व्यापारियों को भरोसा करने और निवेशकों का भरोसा बढाने के लिए Business friendly reform और Ease of Doing Business के प्रयासों से ये सम्भव हुआ है। इसमें जीएसटी, Shop establishment, small, medium के रजिस्ट्रेशन औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा आयोग, डिस्कोम से लेकर बिजली कनैक्शन के लिए आवेदन करना, पानी के कनैक्शन के लिए आवेदन करना निर्माण परमिट पिछले एक वर्ष के दौरान डीपीसीसी की स्थापना और संचालन सम्बन्धी सहमति के आवेदनों को इन सबकी ऑन लाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई। इससे बिजनेस की रैंकिंग में दिल्ली में काफी सुधार हुआ है और मेरा मानना है कि दिल्ली में जो व्यवसाय के लिए माहौल बना उससे World Bank की रैंकिंग में भी इंडिया की रैकिंग इम्प्रूव हुई है। ये बात बीच–बीच में निकलकर सामने आई है। दिल्ली का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार आरम्भ किये जा रहे हैं। ये पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को दिया जाएगा जो अपनी

वस्तु और सेवाओं के निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। उद्योग विभाग डीएसआईआईडीसी द्वारा लीज होल्ड पर आंवटित औद्योगिक परिसम्पतियों से जुड़े किसी भी मामले में विलम्ब से भुगतान पर ब्याज दर 18 परसेंट से घटाकर 10 परसेंट कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सुविधा के लिए 'समाधान' ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए छोटे व्यवसायों के लाभ के लिए सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद को प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 11 परिषदों में बांट दिया गया है ताकि मध्यस्ता से उनके राजस्व में आने वाले विवादों का जल्दी समाधान किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पिछले कुछ वर्षो में एक स्टार्ट–अप केन्द्र के रूप में भी विकसित हुई है। यहां नए–नए युवा, नए तरह के रोजगार, नई तरह की कम्पनियां बना रहे है। सरकार लोगों के बीच entrepreneurship को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे है उनको स्पोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने draft start-up नीति तैयार की है जिसको अब इस साल लागू कर दिया जाएगा।

अब अंत में अध्यक्ष महोदय थोडी बात मैं पर्यटन कला एंव संस्कृति की भी करना चाहता हूं। कला और संस्कृति इन सब पर बात करें तो क्योंकि मैंने अंत में बात की है इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं यहां अंग्रेजी की एक फिल्म है Dead Poets Society, 'Dead Poets Society' एक बडी मशहूर फिल्म है। उनका जो नायक है प्रो0 जोन कीटींग वो एक सीन में अपनी स्टूडेंट्स से कहता है मैं उसका quote-unquote उल्लेख करता हूं उनके डॉयलोग का। वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं प्रो0 साहब "we don't read and write poetry because it's cute. We don't read and write poetry because it's cute, we read and write poetry because we are members of human race and the human race is filled with passion."

अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है "medicine, law, business, engineering, these are nobel pursuits and necessary to sustain life, but art, poetry, duty, love these are what we stay alive for." आदमी जिंदा रहता है इस सब के लिए।

जिंदा रहने के लिए जरूरी साधन है medicine, law, business लेकिन जिंदा रहता है आर्ट के लिए। दृश्य तो अंग्रजी फिल्म का है अध्यक्ष महोदय, लेकिन दर्शन इसमें विशुद्ध भारतीय है। भारत के लोगों ने कला, भाषा, संस्कृति, साहित्य इस सब को जीवन जीने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन के आनंद़ का उद्देश्य माना है इसलिए हमारे तीज, त्योहार से लेकर हमारे तमाम उत्सव कला, संस्कृति से सराबोर होते हैं। हम कभी अपना कोई फेस्टिवल ड्राई नहीं मनाते, कोई बस जाकर फंक्शन कर दिया। हमारे सब में तीज त्यौहार में कला संस्कृति कूट–कूट कर भरी हुई है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षो में कला, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स लागू की हैं। अगले साल दिल्ली सरकार कई नए प्रोग्राम लेकर आ रही है इसमें 'फेस्टिवल ऑफ इंडिया' और 'इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल' का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। देश की सारी भाषाओं की एकेडमियां बनाई जा चुकी हैं। इस साल ये एकेडमियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। इस साल दिल्ली में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो देश भक्ति से सराबोर होंगे। दिल्ली की दीवाली का आयोजन पिछले दो साल से एक ऐसा आकर्षण का केन्द्र बन गया है कि अब लोग दिल्ली सरकार के इस आयोजन का इंतजार करते हैं। दिल्ली की दीवाली इस साल भी बड़े धूमधाम से मनायेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'Delhi Heritage' और 'Promotion of Delhi Tourism Circuit' नाम की दो नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं और दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में branding करने के लिए पिछले साल एक नयी स्कीम नये बजट में प्रस्तावित की थी लेकिन कोविड के कारण उस पर काम नहीं हो पाया, इसको अगले साल लागू करेंगे और सबसे बड़ी चीज कि पर्यटन स्थलों पर महिला सुरक्षा की योजना इस बार पर्यटन विभाग ले के आया है। इसमें पर्यटन स्थलों के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, अंधेरे स्थानों को एलईडी से लाईट करने, डीटीटीडीसी के सारे पर्यटन स्थलों पर यूनिफार्म में सुरक्षा गार्ड की तैनाती, महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर मोबाइल वैन की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल होंगे। मैं इस साल महिलाओं के सुरक्षित बनाने के लिए पांच करोड़ रूपये अलग से राशि रख रहा हूं। लेकिन पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं और स्कीम्स और प्रोजेक्टस के लिए मैं 2021–22 के लिए 521 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब बजट का भाग "ख" प्रस्तुत करता हूं जो रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित है। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉक डाऊन के कारण आई मंदी के असर में मौजूदा वित्त वर्ष में हमारे राजस्व संग्रह में भारी कमी आई थी। जनवरी 2021 तक राजस्व संग्रह बजटीय अनुमान की तुलना में करीब 40 परसेंट नीचे रहा।

2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो सभी राज्यों को पांच साल के लिए 14 परसेंट का Assured Revenue का वादा किया गया था लेकिन Covid Pandemic के नाम पर केन्द्र सरकार इस बार इस वादे से पीछे हट गई बोली ये Act of God है इसमें compensation नहीं दिया जा सकता और उसने फिर दिल्ली सरकार को लोन दिया। दिल्ली सरकार के सामने इस समय दो चुनौती रहेंगी, पहली तो ये कि केन्द्र सरकार कंपेनसेशन के अपने वादे से मुकर गई इसलिए दिल्ली सरकार पर लोन बढ़ रहा है। दूसरा Assured Revenue की सीमा भी जो 5 साल है वो 30 जून 2022 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद राजस्व संग्रह हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं और Data Analytics Business Intelligence का इस्तेमाल करते हुए टैक्स में संभावित किसी भी चोरी को रोकेंगे और इसके लिए जीएसटी के बेहतर implementation के लिए क्या किया जाए उसकी भी स्टडी हम करा रहे हैं। इसमें हमने दिल्ली आने–जाने व्यवसायिक वाहनों पर आरएफआईडी के जरिये नजर रखना शुरू कर दिया है और व्यापारियों के साथ टैक्स के मामलों में एसएमएस के साथ संवाद करना शुरू किया है। दिल्ली में Tax collection बढ़ाने के लिए Excise Policy में भी काफी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इससे जो Non-Duty Paid Liquor होती है बिना ड्यूटी वाली शराब, उसको लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी और दिल्ली में जो liquor shopping है उस पर एक international experience भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभूतपूर्व परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार हमें अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ते हैं। लॉक डाऊन के कारण आई मंदी से उबरने के लिए रियल एस्टेट मार्किट को बढ़ावा देना जरूरी था और रियल एस्टेट मार्किट को बढ़ावा देने के लिए छह महीने के लिए हमने सर्किल रेट में 20 परसेंट की कमी लाने का

फैसला किया है। Nobel पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि real estate sector/ contruction industry, जो है ये unskilled worker के लिए सबसे ज्यादा jobs create करता है इसलिए ये जरूरी था कि हम रियल एस्टेट को मदद करें ताकि इससे गरीबी रोकने में मदद मिले। हमें उम्मीद है कि सर्किल रेट कम करने का जो असर है ये कदम गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी क्रियेट करेगा और हमारा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों की उम्मीद और विकास की रफ्तार केजरीवाल Model of Governance में थमने नहीं दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य के अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के 75 साल में हमारे राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। हमारे लिए ये उत्सव का अवसर भी है और मंथन का अवसर भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अब दिल्ली सरकार काम कर रही है और दिल्ली के आम आदमी की per capita income को सिंगापुर के बराबर ले जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। साफ हवा, साफ पानी, सरकारी हेल्थ सिस्टम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। हम हर दिल्लीवासी के लिए विश्वस्तरीय स्कूल, उच्च शिक्षा और रिसर्च में अवसर देंगे, ये हमारा संकल्प है और जैसा मैंने कहा कि जब हम सौवीं वर्षगांठ मना रहे हों तो दिल्ली ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, ये हमारा सपना, हमारा संकल्प है। रॉबर्ट फ्रास्ट के शब्दों में मैं कहूं : "we have promises to keep and miles to go before whisking" राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गुरूदेव रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा 110 साल पहले कहे गए शब्द उनको मैं यहां दोहरा के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 110 साल पहले उन्होंने कहा था

Where the mind is without fear and the head is held high;

Where the knowledge is free;

Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls;

Where words come out from the depth of truth;

Where tireless striving stretches its arms towards perfection;

Where the clear stream of reason has not lost its way
into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by thee
into ever-widening thought and action

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

जहां मन हो भय से मुक्त

और सर हो फख्र से ऊंचा,

जहां ज्ञान हो मूर्खताओं से आजाद

जहां न हो दुनिया बिखरी हुई और बंटी हुई

संकीर्ण और घटिया सोच की दीवारों के बीच

जहां सच की गहराई से निकलकर बाहर निकलें शब्द

जहां कोशिशें बिना थके फैलायें अपनी बाहें

सबसे बेहतरीन को पाने की खातिर

जहां मुर्दा आदतों की सूखी रेत में

उम्मीदों की निर्मल धाराएं

न भटकें अपनी राहें जहां निरंतर खुले विचार और कर्मों की ओर

मन बढ़ता रहे आगे ।

हे परमपिता परमेश्वर आजादी के उसी स्वर्ग में

मेरे विश्व को, मेरे देश को जागृत कर

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सदन के विचार के लिए सौंपता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अनुदानों की मांगें 2021–2022 अब माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए Demands for Grants पेश करेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः- Hon'ble Speaker sir, I present Demands for Grants for the financial year 2021-22 before this House.

अध्यक्ष महोदयः इन अनुदान मांगों पर सदन में 12 मार्च 2021 को विचार किया जाएगा। अनुदानों की पूरक मांगे वर्ष 2020–2021 अब माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश करेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I present first and final batch of supplementary Demands for Grants for the financial year 2020-21 before this House.

अध्यक्ष महोदयः बैठिये सर, बैठिये। अब सदन सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर डिमांड वाईज विचार करेगा।

DEMAND NO. 2 (General Administration)

जिसमें Revenue में 4 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 2 पास हुई।

DEMAND NO. 3 (Administration of Justice)

जिसमें Revenue में 62 करोड़ 78 लाख रुपये तथा Capital में 15 करोड़ रूपये हैं, कुल राशि 77 करोड़ 78 लाख रुपये सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 3 पास हुई।

DEMAND NO. 4 (Finance)

जिसमें Revenue में 6 लाख रुपये तथा Capital में 1 लाख रूपये हैं, कुल राशि 7 लाख रुपये सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 4 पास हुई।

DEMAND NO. 5 (Home)

जिसमें Revenue में 25 करोड़ 26 लाख 50 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 5 पास हुई।

DEMAND NO. 6 (Education)

जिसमें Revenue में 38 लाख रुपये हैं तथा Capital में 1 लाख रूपये हैं, कुल राशि 39 लाख रुपये सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 6 पास हुई।

DEMAND NO. 7 (Medical & Public Health)

जिसमें Revenue में 1 अरब 1 करोड़ 40 लाख 3 हज़ार रुपये तथा Capital में 15 करोड़ 68 लाख 25 हज़ार रूपये हैं, कुल राशि 1 अरब 17 करोड़ 8 लाख 28 हज़ार रुपये सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 7 पास हुई।

श्री ओमप्रकाश शर्माः सर जी कोई डिटेल तो दे दो वैसे ही हां, न करवाए जा रहे हो।

माननीय अध्यक्षः मैं डिटेल दे रहा हूं न आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक–एक चीज सुना रहा हूं। एक–एक चीज मैं आपको सुना रहा हूं। चलिये, इसको समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ओमप्रकाश जी। डिमांड नं0 8, क्लीयर समझिए। डिमांड नं0 8 सोशल वेल्फेयर। दो मिनट झा साहब नहीं प्लीज।

DEMAND NO. 8 (Social Welfare)

जिसमें Revenue में 32 लाख 50 हज़ार रूपये तथा Capital में 1 लाख रूपये, कुल राशि 33 लाख 50 हज़ार रूपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 8 पास हुई।

DEMAND NO. 9 (Industries)

जिसमें Revenue में 2 अरब 70 करोड़ 50 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 9 पास हुई।

DEMAND NO. 10 (Development)

जिसमें Revenue में 2 अरब 80 करोड़ 52 लाख 19 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 10 पास हुई।

DEMAND NO. 11 (Urban Development & Public Works)

जिसमें Revenue में 87 करोड़ 93 लाख 16 हज़ार रूपये तथा Capital में 23 लाख रूपये, कुल राशि 88 करोड़ 16 लाख 16 हज़ार रूपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर Revenue में 8 अरब 28 करोड़ 70 लाख 88 हज़ार रुपये तथा Capital में 30 करोड़ 94 लाख 25 हज़ार, कुल राशि 8 अरब 59 करोड़ 65 लाख 13 हज़ार रुपयों की Supplementary Demands को मंजूरी दे दी है।

Appropriation (No. 1) Bill, 2021

(Bill No. 01 of 2021)

माननीय अध्यक्षः– अब माननीय उप मुख्यमंत्री Appropriation (No. 1) Bill, 2021 (Bill No. 01 of 2021) को House में Introduce करने की permission मांगेंगे।

Hon'ble Dy. Chief Minister:- Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (No. 1) Bill, 2021 (Bill 01 of 2021) to the House.

मननीय अध्यक्षः– माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री Bill को सदन में Introduce करेंगे।

Hon'ble Dy. Chief Minister:- Hon'ble Speaker Sir, I introduce Appropriation (No. 1) Bill, 2021 (Bill No. 01 of 2021) to the House.

अध्यक्ष महोदय – अब Bill पर Clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2, खण्ड–3 व Schedule बिल का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड–2, खण्ड–3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड–1, Preamble और Title Bill का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड–1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation (No. 1) Bill, 2021 (Bill No. 01 of 2021) को पास किया जाए।

Hon'ble Dy. Chief Minister:- Hon'ble Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriation (No. 1) Bill, 2021 (Bill No. 01 of 2021)

माननीय अध्यक्षः– माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Appropriation (No. 1) Bill, 2021(Bill No. 01 of 2021) पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः समिति के प्रतिवेदन पर सहमति।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष जी एक हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है

माननीय अध्यक्षः अभी–अभी मैं इसपे कह चुका डायरेक्शन दे चुका।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः .....मामला है..... ज्यादा नहीं बोलने दिया गया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी। विजेंद्र जी मैं कल इन पर चर्चा कराउंगा। कल समय दूंगा इनपर। इनपर सारी चर्चाएं होंगी। नहीं ऐसे नहीं। मैंने अलाऊ नहीं किया, मैंने कल पर रखा है। कल मंत्री जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिए विजेंद्र जी ऐसे हाउस नहीं चल सकेगा। मैं बड़े प्यार से इज्जत से कल आपको जवाब देंगे न जी। कल आ रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिष्ट जी मैंने कहा है कल आपको समय मिलेगा इसके लिए। अब मैं कुछ नहीं। अभी मुझे आज का बिजनेस पूरा करने दीजिए प्लीज। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप बोल लीजिए। विजेंद्र जी आप बोल लीजिए जितना। कोई बात नहीं। कल उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलिए। माननीय सदस्यगण ध्यान देंगे, भई। उधर छोड़ दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। मुझे आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार के...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं उसको सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं सुन लीजिए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। मुझे आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार के सूचना प्रौधोगिकी विभाग ने सभी माननीय सदस्यों को टेबलेट उपलब्ध करवाएं हैं। माननीय, भई आप छोड़ दीजिए, झा साहब नो टिप्पणी एट ऑल, कोई टिप्पणी न करिए। कोई टिप्पणी न करिए, बैठिए आप आराम से प्लीज। माननीय उपमुख्यमंत्री का बजट भाषण अब ध्यान से। चलिए।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः भाई सदस्यगण, थोड़ा ध्यान दे लें बहुत महत्वपूर्ण विषय है फिर बाद में दिक्कत आएगी आपको। त्रिपाठी जी प्लीज। माननीय उपमुख्यमंत्री का बजट भाषण तथा संबंधित दस्तावेज टेबलेट पर उपलब्ध रहेगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि टेबलेट पर दिल्ली बजट एप का आइकॉन प्रेस कर दें और इससे उन्हें सभी बजट दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में भी यह एप उपलब्ध है और माननीय सदस्य अपने मोबाईल या लेपटोप में इस एप को डाउनलोड करके बजट के दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि उनको आज सदन स्थगित होने के बाद टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र संख्या 1 से 25 के विधायक यानि एसी 1 टू 25 के विधायक एमएलए लॉज

संख्या 2 मेरे दायीं ओर से लेंगे और 26 से 70 तक के सभी विधायक मेरे बायीं ओर के लॉज नम्बर 1 से अपने टेबलेट ले सकेंगे और ये तीन बजे तक उपलब्ध रहेंगे। माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे इस सत्र की सभी बैठकों के दौरान अपना टेबलेट लेकर आए ताकि उनको सत्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज सुलभ हो सकें। हम पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और सदस्यों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑन लाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। समिति के प्रतिवेदन पर सहमति सुश्री राखी बिड़ला जी, दिलीप कुमार पांडेय जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 08 मार्च 2021 को प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

सुश्री राखी बिरलाः अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन दिनांक 08 मार्च 2021 को प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के प्रति प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन। मैं माननीय मुख्यमंत्री से श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि समितियों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम–192 के उप नियम–2, नियम–194 के उप नियम–2 और नियम 196 के उप

नियम–2 के अनुसरण में, इस सदन के सदस्य 01 अप्रैल 2021 से आरम्भ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं।

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव सदन के समाने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः जरनैल सिंह जी की ओर से एक रिक्वेस्ट आई है कि केक काटा जाएगा इसलिए सभी विधायक एमएलए लॉज 1 में सादर आमंत्रित हैं। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पूर्व आज फाइनेंस मंत्रालय माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से लंच की व्यवस्था है। जो हमारा कॉफ्रेंस हॉल है उसके बेक साइड में हम सभी लंच के लिए जाएंगे। मीडिया के बंधुओं के लिए सामने वाले पार्क में लंच की व्यवस्था रहेगी। अब सदन की कार्यवाही 10 मार्च 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत –बहुत धन्यवाद, सभी सदस्यों का धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 10 मार्च, 2021 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

–समाप्त–

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, स्मैट फॉर्म्स, नई दिल्ली–110 007 द्वारा मुद्रित।